हिंदी दैनिक

कलम की पहल

PRGI NO. UAHIN/25/A1323

वर्ष : 02 अंक : 154 पृष्ठ : 08 मूल्य : 1 रूपए नैनीताल, रविवार, 22 नवंबर, 2026

E-mail: kalamkipahaluk@gmail.com Website: kalamkipahal.com

US रिपोर्ट में 'ड्रैगन' बेनकाब !

भारत के खिलाफ साजिश, पाक को मोहरा बना रहा चीन

नई दिल्ली। अमेरिका के एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में भारत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को चीन से समर्थन मिलने का जिक्र किया गया है. हालांकि, इस बीच भारत-चीन के बीच अविश्वास अभी भी काफी बना हुआ है. पाकिस्तान के साथ चीन की बढ़ती सैन्य साझेदारी ने भारत के लिए टू-फ्रंट वॉर की स्थिति बना दिया है, जो चिंता की बात है.



ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मई 2025 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष ने दिखाया कि कैसे चीन, सीधे लड़ाई में शामिल हुए बिना, संकट के समय पाकिस्तान को मदद पहुंचा सकता है. इससे भारत की यह चिंता और बढ़ गई है कि भविष्य में पाकिस्तान के साथ कोई संघर्ष में चीन मदद पहुंचा सकता है.

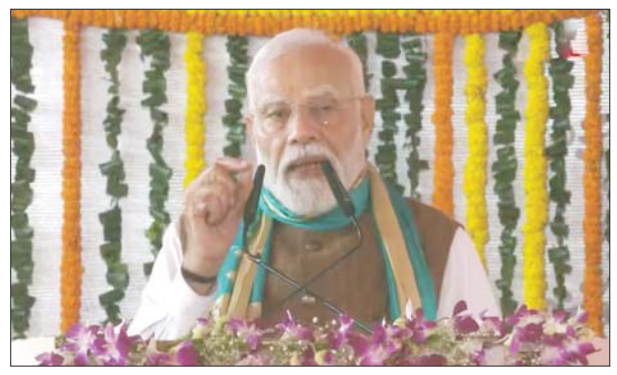
अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है, जिसके पास ऐसी अच्छी-खासी आबादी, आर्थिक, सैन्य और भौगोलिक क्षमता है. ये चीन की ताकत को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है. चीन भारत के डेवल्पमेंट को चुनौती के रूप में देखता है. उसे सीमित करने के लिए सैन्य, आर्थिक, समुद्री और अन्य प्रकार के दबाव डाल रहा है.

चीन के साथ भारत की प्रतिद्वंद्विता के पीछे उसके अपने हित हैं. इस बीच चीन-भारत संबंधों में सीमा विवाद अब तक के तनाव का सबसे बड़ा कारण है. 2020 में गलवान घाटी की झड़पें एक बड़ा मोड़ साबित हुई, जिसके बाद भारत अब क्षेत्रीय विवाद को चीन के साथ अपने व्यापक संबंधों से अलग रखने के लिए तैयार नहीं है.

सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश

साल 2020 के 4 साल बाद यानी 2024 के अंत से भारत-चीन ने धीरे-धीरे अपने संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की है. हालांकि, इसके बावजूद दोनों देशों के बीच अविश्वास की स्थिति बनी हुई है. भारत का मानना है कि व्यापक स्तर पर सामान्य संबंध बहाल करने के लिए सीमा पर शांति होना अनिवार्य है। इसको लेकर कई बैठक भी हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने-अपने स्तर से सीमा विवाद को सुलझाने के लिए शांति के अथक प्रयास भी किए.

'तब घोटाले गिने जाते थे, आज निवेश के आंकड़े आते हैं, वैशाली में पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा



वैशाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के वैशाली में लगभग 34,470 करोड़ रुपये की लागत वाली कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इसमें 9.76 किलोमीटर लंबे छह लेन के 'नीतीश सेतु' का उद्घाटन भी शामिल है. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दलों को मिलकर समृद्ध और आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए लगातार काम करना है.

जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि इतनी विशाल भीड़ को कोई भी कैमरा पूरी तरह से कैद कर पाएगा. यह जनसैलाब इस बात का जीता-जागता सबूत है कि लोगों में विकास के प्रति जागरूकता और समर्पण लगातार बढ़ रहा है. लोक आस्था का महापर्व 'छठ' अभी-अभी संपन्न हुआ है... और अब छठी मैया के आशीर्वाद से हम यहां विकास का उत्सव मनाने के लिए जुटे हैं.'

पीएम मोदी ने कहा, 'लगभग तीन दशक पहले, बिहार ने एक नया उम्मीद और भरोसे का रास्ता चुना था. दशकों तक कठिनाइयां झेलने वाले बिहार में, नीतीश जी के नेतृत्व में सुशासन के प्रति एक नया विश्वास जागा. नीतीश जी ने कई सालों तक मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की सेवा की. अब उन्हीं के आशीर्वाद से सम्राट चौधरी और उनकी पूरी टीम इस मिशन को आगे बढ़ा रही है. इसी भावना के साथ, आज यहां हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है. मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे मित्र रामविलास जी की आत्मा जहां कहीं भी होगी, वे आज हम पर फूल बरसा रहे होंगे, क्योंकि हम उनके सपनों को साकार कर रहे हैं.'

विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'एनडीए के शासन से पहले समय कैसा होता था. तब गिनती घोटालों की होती थी, लेकिन आज बिहार में हो रहे निवेश के आंकड़े पेश किए जाते हैं. तब आंकड़े अपराधों के आते थे, अब अपराधियों पर कार्रवाई की बात आती है चर्चा में. एनडीए के शासन में विकास की होड़ दिखती है.

पीएम मोदी ने कहा, 'गंगा मैया पर बने दरगाह-बिदुपुर छह-लेन केबल ब्रिज को जनता के लिए समर्पित किया गया है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी को अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि









नमामि गंगे घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार एवं धार्मिक विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ अंतिम संस्कार, छोटे पुत्र महेंद्र बिष्ट ने दी मुखाग्नि

मुख्यमंत्री श्री धामी ने श्री योगी आदित्यनाथ एवं उनके परिजनों से भेंट कर व्यक्त की शोक संवेदनाएं, दिवंगत पुण्यात्मा की शांति के लिए की प्रार्थना

के.के.पी संवाददाता

हरिद्वार। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हरिद्वार स्थित नमामि गंगे घाट पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की माताजी स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी के अंतिम दर्शन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री योगी आदित्यनाथ एवं उनके परिजनों से भेंट कर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि माता का स्नेह, आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन जीवन की अमूल्य धरोहर है। उनका निधन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने बाबा केदार से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोक संतप्त परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। नमामि गंगे घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार एवं धार्मिक विधि-विधान के साथ स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। उनके छोटे पुत्र श्री महेंद्र बिष्ट ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर देशभर से पहुंचे जनप्रतिनिधियों, विभिन्न राज्यों के मंत्रियों, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों, धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत की विभूतियों तथा संत-महात्माओं ने अंतिम दर्शन कर पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। संत समाज की ओर से परम पूज्य योगऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, संस्थापक पतंजलि योगपीठ, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, महामंत्री पतंजलि योगपीठ एवं प्रबंध निदेशक पतंजलि आयुर्वेद, श्रीमहंत रविंद्र पुरी जी महाराज, अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं अध्यक्ष श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट, हरिद्वार, परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, अध्यक्ष परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश तथा श्रीमहंत डॉ. रविंद्र पुरी जी महाराज, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी ने महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरि जी महाराज, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आध्यात्मिक गुरु एवं श्री कल्कि धाम के पीठाधीश्वर, श्रीमहंत रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज, परम पूज्य बाबा हठयोगी जी महाराज, स्वामी दर्शन भारती जी महाराज, श्रीमहंत संजय जी महाराज, महंत ऋषिश्वरानंद महाराज तथा स्वामी कल्याण देव महाराज सहित अनेक संत-महात्माओं ने भी अंतिम दर्शन कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक एवं श्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी, जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह, श्री बृजेश सिंह, पर्यावरण एवं वन विभाग से संबंधित मंत्री श्री के.पी. मलिक, आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु', राज्यमंत्री श्री दिनेश खटीक, श्री सुनील कुमार शर्मा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग श्री दिनेश प्रताप सिंह, राज्यमंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी, पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह तथा कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग के राज्यमंत्री श्री बलदेव सिंह औलख, हरिद्वार सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गोरखपुर सांसद श्री रवि किशन, श्री सुरेंद्र दिलेर, वन एवं पर्यावरण विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी एवं डॉ. धन सिंह रावत, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, रुड़की विधायक श्री प्रदीप बत्रा, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' तथा भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल,प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों में उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन, एडीजी श्री ए.पी. अंशुमान, आईजी गढ़वाल श्री राजीव स्वरूप, कुंभ मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका तथा जिलाधिकारी हरिद्वार श्री मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, भरी संख्या में जनसमूह मौजूद रहे। सभी ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत पुण्यात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

अविवाहित माता-पिता वाले बच्चे पर मां का ज्यादा हक, सुप्रीम कोर्ट ने बाप को बाद में रखा



नई दिल्ली। बिना शादी बच्चे को जन्म देने वालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अविवाहित माता-पिता से जन्में बच्चे की कस्टडी (संरक्षण) के लिए मां का दावा पहली नजर में अधिक मजबूत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि न भारतीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों में भी अविवाहित माता-पिता की संतान की कस्टडी के लिए मां के अधिकार को ही प्राथमिकता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूके के कानून का भी उदाहरण दिया। बेंच ने चार साल के बच्चे को उसकी जर्मन मां को सौंपते हुए यह टिप्पणी की है। मां अपने बेटे को सिंगापुर ले जाना चाहती थी, जहां वह काम करती है। जबकि बच्चे के भारतीय पिता ने महिला की मांग का विरोध करते हुए कहा कि बच्चे को देश से बाहर नहीं जाने दिया जाए। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि 'अविवाहित माता-पिता से जन्म लेने वाले संतान की कस्टडी के लिए मां का दावा प्रथम दृष्टया अधिक मजबूत होता है।' हालांकि अदालत ने फैसले में यह स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल अंतरिम कस्टडी के लिए मां के प्रथम दृष्टया दावे तक सीमित है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेटा के दफ्तर में मचाई तोड़फोड़, नारे लगाकर काटा बवाल; 7 दिन का अल्टीमेटम देकर लौटे

हैदराबाद। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मालिकाना हक वाली कंपनी मेटा के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है. यूथ कांग्रेस के लोगों ने शुक्रवार को मुंबई, हैदराबाद और गुरुग्राम में प्रदर्शन किया. इस दौरान उन पर हैदराबाद स्थित कंपनी के कार्यालय में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है. इसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इसमें कांग्रेस के लोग गमले उठाकर फेंकते नजर आ रहे हैं. इसके अलावा दफ्तर के कैफेटिरिया के पास तक पहुंच गए और जमकर हंगामा काटा. मेटा डाउन डाउन के नारे लगाते हुए कुछ देर ये लोग धरने पर भी बैठ गए. यूथ कांग्रेस ने मेटा पर भेदभाव का आरोप लगाया है और 7 दिन में रवैया सुधार लेने का अल्टिमेटम दिया.

हैदराबाद में यूथ कांग्रेस के लोग प्रदेश अध्यक्ष जे. शिवचरण रेड्डी के नेतृत्व में कार्यकर्ता मेटा ऑफिस पहुंचे थे. इन लोगों ने मेटा और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इन लोगों का आरोप था कि मेटा का एल्गोरिदम मनमानी भरा है और सरकार के इशारों पर काम हो रहा है. इन लोगों ने कहा कि मेटा को भाजपा के दबाव से बचना चाहिए.

'मेरे सामने कई लड़के मारे गए', धोखे से रूस के चंगुल में फंसा भारतीय; यूक्रेन में किया सरेंडर

कीव। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच एक और भारतीय नागरिक के यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण करने का मामला सामने आया है। पंजाब के जालंधर के रहने वाले 40 वर्षीय गुरप्रीत सिंह रंधावा को यूक्रेनी सेना ने अपने कब्जे में लिया है। आरोप है कि उन्हें रूस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बुलाया गया और बाद में रूसी सेना में भर्ती कर युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन में मौजूद सूत्रों के हवाले से गुरप्रीत



सिंह रंधावा की पहचान की गई है। इसी सप्ताह यूक्रेन के यूट्यूबर वोलोदिमिर जोल्किन ने उनका करीब एक घंटे का इंटरव्यू भी किया। जोल्किन इससे पहले भी रूसी सेना के कब्जे में आए कई युद्धबंदियों का इंटरव्यू कर चुके हैं। इंटरव्यू के दौरान गुरप्रीत कई बार भावुक होकर रो पड़े। इस वीडियो को यूक्रेन सरकार की परियोजना 'आई वांट टू लिव' ने भी शेयर किया है। यह परियोजना युद्धबंदियों के मामलों से जुड़े यूक्रेनी सरकारी समन्वय मुख्यालय के तहत काम करती है।

यूक्रेन की 'आई वांट टू लिव' परियोजना के मुताबिक, गुरप्रीत सिंह रंधावा को रूस में नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन देखा था, जिसमें कपड़ों की फैक्ट्री में ड्राइवर की नौकरी देने का वादा किया गया था। इसके बाद उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया। एक रिक्रूटर ने उन्हें रोजगार दिलाने का भरोसा दिया। परियोजना की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसारः

गुरप्रीत को रूस जाने के लिए टूरिस्ट वीजा दिलाने में मदद की गई। उनके लिए हवाई टिकट खरीदे गए।

रूस पहुंचने पर दिखाने के लिए उन्हें 500 डॉलर भी दिए गए।

26 अगस्त 2026 को उन्होंने रूसी सशस्त्र बलों के साथ सैन्य सेवा का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया।

BJP के OBC मोर्चा के लिए नए पदाधिकारियों की लिस्ट जारी, जानें किस-किस को मिली बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शनिवार को अपने OBC मोर्चा के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों की लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने ङ्क प्लेटफॉर्म पर पदाधिकारियों और सदस्यों के नामों के साथ उनकी नियुक्ति की जानकारी साझा की है. BJP की तरफ से जारी आधिकारिक लिस्ट के मुताबिक, पार्टी ने OBC मोर्चा के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री, राष्ट्रीय सह-कार्यालय मंत्री, मीडिया संयोजक, सोशल मीडिया संयोजक, सोशल मीडिया सह-संयोजक, नीति एवं शोध संयोजक, नीति एवं शोध सह-संयोजक, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य और राष्ट्रीय कार्यसमिति - विशेष आमंत्रित पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति की है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के ओबीसी मोर्चा के लिए कुल 7 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है. इसमें जोगेन मोहन को असम, ममता मोहंता को ओडिशा, संगम लाल गुप्ता को उत्तर प्रदेश, बबनराव रावजी चौधरी को महाराष्ट्र, सत प्रकाश राणा को दिल्ली, डॉ. अर्जुन साहनी को बिहार और संगीता बलवंत बिंद को उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, गजेंद्र यादव को दिल्ली, प्रमोद मध्वराज को कर्नाटक, ललित चंद्राकार को छत्तीसगढ़ में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही, दशरथजी ठाकोर को गुजरात, टी. वरथराजन को तमिलनाडु, संजीव कुमार (बबलू भगत) को झारखंड, सरिता जांगिड़ को हरियाणा, कडगंची रमेश को तेलंगाना, वैभव पंवार को मध्य प्रदेश और भीम कुमार साहू को बिहार में राष्ट्रीय मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब शिक्षकों के कंधों पर, चंपावत में दिया गया कानूनी प्रशिक्षण

पॉक्सो एक्ट और बाल संरक्षण कानूनों की दी जानकारी, स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित माहौल देने पर जोर।

के.के.पी संवाददाता

चंपावत। बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 'सुरक्षित बचपन अभियान' के दूसरे चरण के तहत शनिवार को जिला न्यायालय सभागार में शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जनपद के चयनित विद्यालयों के शिक्षकों को बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों और उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई।



कार्यक्रम का शुभारंभ जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में शिक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षक न केवल बच्चों को शिक्षा देते हैं, बल्कि उनके व्यवहार में आने वाले बदलावों को पहचानकर उन्हें किसी भी तरह के शोषण और उत्पीड़न से बचाने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं।

प्रशिक्षण के दौरान सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने किशोर न्याय अधिनियम-2015 और बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने पॉक्सो एक्ट-2012 के प्रावधानों, बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न की पहचान करने के तरीकों के साथ ऐसी घटनाओं की जानकारी मिलने पर की जाने वाली कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया। निर्धारित विशेष मॉड्यूल के तहत आयोजित प्रशिक्षण में शिक्षकों को मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी जागरूक किया गया। साथ ही उनसे प्रशिक्षण में मिली जानकारी को विद्यार्थियों, अभिभावकों और समाज के अन्य लोगों तक पहुंचाने की अपेक्षा की गई, ताकि बच्चों को शोषण, उत्पीड़न और भय से मुक्त सुरक्षित वातावरण मिल सके।

बंजरखेत और मंडलसेरा में चला विशेष स्वच्छता अभियान, नागरिकों से की गई सफाई बनाए रखने की अपील





के.के.पी संवाददाता

जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे के निर्देशों के क्रम में जनपद में प्रत्येक शनिवार को संचालित किए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान के तहत शनिवार को बंजरखेत एवं मंडलसेरा क्षेत्र में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया।

अभियान के नोडल अधिकारी एवं जिला पंचायती राज अधिकारी प्रकाश कांडपाल के नेतृत्व में नगर पालिका के कर्मचारियों ने क्षेत्र में साफ-सफाई, कूड़ा एकत्रीकरण एवं कूड़ा निस्तारण का कार्य किया।

इस अवसर पर जिला पंचायती राज अधिकारी प्रकाश कांडपाल ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए सामूहिक सहभागिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने नागरिकों से अपने घरों एवं आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की।

मनोनीत सभासद ज्योति दीप नारायण ने बताया कि नगर पालिका द्वारा नवंबर माह में विशेष सफाई अभियान संचालित किया जा रहा है। नगर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पालिका के कर्मचारी नियमित रूप से सफाई कार्यों में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान तभी सफल होगा, जब आमजन भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने नगरवासियों से अपील की कि वे अपने घरों का कूड़ा इधर-उधर न फेंककर नगर पालिका के कूड़ा संग्रहण वाहनों अथवा निर्धारित माध्यमों से ही निस्तारित करें।

एक नजर

किसानों की समस्याओं को लेकर डॉ. गणेश उपाध्याय ने सरकार को घेरा, खाद की किल्लत और किसान आईडी की तकनीकी खामियों पर उठाए सवाल

के.के.पी संवाददाता/किच्छा। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री डॉ. गणेश उपाध्याय ने प्रदेश के किसानों की वर्तमान स्थिति को लेकर राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की है। एक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण किसानों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। डॉ. उपाध्याय ने आरोप लगाया कि यूरिया, एनपीके और डीएपी सहित विभिन्न प्रकार की खादों के मूल्यों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसानों की खेती की लागत बढ़ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि खाद की उपलब्धता न होने के कारण किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने किसान आईडी (फार्मर आईडी) बनाने की प्रक्रिया में आ रही तकनीकी खामियों का मुद्दा भी उठाया। उनके अनुसार, पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों के कारण किसान अपना पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं, और जिन किसानों की कृषि भूमि दो अलग-अलग ग्राम सभाओं में स्थित है, उन्हें विशेष रूप से अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गन्ना किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने सितारगंज से भाजपा विधायक एवं प्रदेश के गन्ना मंत्री पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक गन्ने का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका है, जिससे क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। डॉ. उपाध्याय ने प्रशासन से किसानों की इन व्यावहारिक और तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की है।



ऐक्टू की 22 नवंबर की देहरादून रैली में आशा, औद्योगिक मजदूर, ठेका श्रमिक, निर्माण मजदूर बड़ी संख्या में शामिल होंगे

के.के.पी संवाददाता/हल्द्वानी। ऐक्टू के आह्वान पर आशाओं समेत सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन, पेंशन, नियमितीकरण, 4 लेबर कोड की वापसी, ठेका प्रथा की समाप्ति, सामजिक सुरक्षा, बीमा, और अन्य मांगों के संबंध में 22 नवंबर को देहरादून में रैली व धरना-प्रदर्शन कर अपनी मांगों को उठाया जायेगा और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा. इस रैली में नैनीताल जिले से आशा वर्कर्स, औद्योगिक मजदूर, ठेका श्रमिक, निर्माण मजदूर भी देहरादून रैली में शामिल होंगे. उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन (सम्बद्धः ऐक्टू) के प्रदेश महामंत्री डॉ कैलाश पाण्डेय ने कहा कि, भाजपा की सरकार को राज्य में 10 साल पूरे हो चुके हैं, जिसमें से धामी जी को मुख्यमंत्री रहते हुए 6 साल बीत चुके हैं. इस दौरान कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आशा वर्कर्स ने सरकार को कई बार ज्ञापन भेजे, कई जगहों पर आशा यूनियन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपे. लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि आशाओं पर काम का बोझ तो लगातार बढ़ाया जा रहा है लेकिन उत्तराखण्ड के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशाओं को न्यूनतम वेतन, कर्मचारी का दर्जा कुछ भी नहीं मिलता जो कि बिल्कुल अनुचित और अन्यायपूर्ण है.

मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक, 04 जनवरी को होगा अंतिम सूची का प्रकाशन

के.के.पी संवाददाता

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर संचालित मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संपादन को लेकर अपर जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह विष्ट की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के एकीकृत प्रारूप प्रकाशन, दावे एवं आपत्तियों तथा संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई।



अपर जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने, संशोधन एवं अपात्र नामों को हटाने के लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर, 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा तथा अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 04 जनवरी, 2027 को होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अभियान के दौरान पात्र मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा किसी भी पात्र मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज होने से वंचित न रहने देने के निर्देश दिए।

अपर जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग करने तथा अपने बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) के माध्यम से निर्वाचक नामावली की जांच एवं सत्यापन में सहयोग देने की अपील की।

बैठक में भाजपा के प्रतिनिधि मदन राम आगरी, कांग्रेस के प्रतिनिधि ईश्वर चंद्र पांडे, प्रवीन सिंह कोरंगा, सहायक निर्वाचन अधिकारी धनी राम टमटा उपस्थित रहे।

उत्तरी कमान में आर्मी पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा का परचम, प्राप्त किए तीन प्रतिष्ठित पुरस्कार

के.के.पी संवाददाता

अल्मोड़ा। आर्मी पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा ने उत्तरी कमान प्रधानाचार्य सम्मेलन-2026 में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों का परचम लहराते हुए तीन प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए हैं। यह सम्मेलन बीती 18 और 19 नवंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल, ओल्ड कैंट, प्रयागराज में आयोजित किया गया। विद्यालय को सत्र 2025-26 की कक्षा दसवीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उत्तरी कमान के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मुख्यालय उत्तरी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ द्वारा प्रतिष्ठित रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य सुशील जोशी को उत्कृष्ट नेतृत्व एवं शैक्षणिक प्रशासन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रधानाचार्य पुरस्कार तथा शिक्षिका माया जोशी को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया। एक ही सम्मेलन में विद्यालय को तीन महत्वपूर्ण पुरस्कार मिलना उसकी शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षकों की प्रतिबद्धता, विद्यार्थियों की मेहनत और विद्यालय प्रबंधन के कुशल मार्गदर्शन को दर्शाता है। इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार में हर्ष एवं उत्साह का माहौल है। प्रधानाचार्य सुशील जोशी ने इस गौरवपूर्ण सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के समर्पण, अभिभावकों के सहयोग तथा विद्यालय प्रबंधन के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने भविष्य में भी शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संकल्प व्यक्त किया। विद्यालय की यह उपलब्धि आर्मी पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा के साथ ही समस्त अल्मोड़ा क्षेत्र के लिए भी गौरव का विषय है।



अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के डॉ. सुमित जीना ने अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दिया व्याख्यान

के.के.पी संवाददाता

अल्मोड़ा। सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा के चिकित्सक डॉ. सुमित जीना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थान और देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी शोध उपलब्धि दर्ज कराई है। उनके शोध पत्र का चयन अमेरिका के शेरिडन में आयोजित 'अंतरराष्ट्रीय बाल रोग एवं नवजात विज्ञान सम्मेलन' के लिए हुआ, जहां उन्होंने 20 और 21 नवंबर को अपने शोध विषय पर व्याख्यान दिया। डॉ. सुमित जीना नवजात शिशु रोग (नियोनेटोलॉजी) के सुपर-स्पेशलिस्ट चिकित्सक हैं। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली से पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी (बाल उदर एवं पाचन रोग विज्ञान) में फेलोशिप भी प्राप्त की है। वर्तमान में वह संस्थान के बाल रोग एवं नवजात विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉ. सुमित जीना के शोध पत्र का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए चयन और वहां व्याख्यान देना अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। उनकी इस उपलब्धि से संस्थान के चिकित्सकों की शोध एवं चिकित्सा क्षेत्र में सक्रिय भूमिका को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली है। इस उपलब्धि पर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. तितियाल ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए गर्व का क्षण है कि संस्थान के चिकित्सक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान का मान बढ़ा रहे हैं।



बाल वैज्ञानिकों ने दिखाया हुनर, विज्ञान महोत्सव में नवाचार और वैज्ञानिक सोच का प्रदर्शन

के.के.पी संवाददाता

अल्मोड़ा। जनपद में जिला स्तरीय विज्ञान महोत्सव 2026-27 का आयोजन पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में किया गया। महोत्सव में जनपद के विभिन्न विद्यालयों से 400 से अधिक बाल वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग कर अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा, नवाचार एवं रचनात्मक सोच का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के तहत विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान ड्रामा आयोजित किए गए। विज्ञान प्रदर्शनी जूनियर एवं सीनियर वर्ग में आयोजित हुई। विद्यार्थियों ने सात उपविषयों के अंतर्गत विज्ञान आधारित मॉडल, प्रयोग और नवीन विचार प्रस्तुत किए। इनमें बेहतर जीवन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण, गणितीय प्रतिरूपण एवं कम्प्यूटेशनल चिंतन, स्वास्थ्य-स्वच्छता एवं साफ-सफाई, स्वदेशी कृषि पद्धतियां, ग्रामीण परिवर्तन के लिए विज्ञान तथा आपदा प्रबंधन जैसे विषय शामिल रहे। विद्यार्थियों ने अपने मॉडल एवं प्रस्तुतियों के माध्यम से विज्ञान और तकनीक के उपयोग से दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान, पर्यावरण संरक्षण, कृषि विकास, ग्रामीण जीवन में सुधार तथा आपदा के प्रभावों को कम करने के उपायों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। विज्ञान ड्रामा के माध्यम से भी विद्यार्थियों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक जागरूकता और विज्ञान के महत्व को रोचक तरीके से अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य शिक्षा अधिकारी हरक राम कोहली ने कहा कि विज्ञान महोत्सव विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा, नवाचार एवं समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने का महत्वपूर्ण मंच है। आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहकर प्रयोग, अवलोकन और अनुसंधान के माध्यम से सीखने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। उन्होंने बाल वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत मॉडलों की सराहना करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के छोटे-छोटे वैज्ञानिक प्रयास भविष्य में बड़े आविष्कारों का आधार बन सकते हैं।



विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य मानव जीवन को सरल, सुरक्षित एवं बेहतर बनाना है। उन्होंने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत, स्वच्छता, कृषि एवं ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में विज्ञान के उपयोग के लिए प्रेरित किया तथा शिक्षकों से विद्यार्थियों की वैज्ञानिक प्रतिभा को निरंतर प्रोत्साहित करने का आह्वान किया।

निर्मला कॉन्वेंट स्कूल के वार्षिकोत्सव 'ऐक्य' में दिखी भारतीय सांस्कृतिक एकता की अनुपम छटा

के.के.पी संवाददाता

हल्द्वानी। निर्मला कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, काठगोदाम का वार्षिकोत्सव 'ऐक्य' हर्षोल्लास एवं भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की थीम भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता को समर्पित रही। पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण भारत की विभिन्न संस्कृतियों को एक मंच पर प्रस्तुत कर विद्यार्थियों ने प्रेम, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। समारोह में मुख्य अतिथि कुमाऊँ आयुक्त दीपक रावत तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपकुलपति डॉ. सतपाल सिंह एवं डीआईजी, सीआरपीएफ किशोर प्रसाद उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त जोगेंद्र रौतेला, फादर पायस (डीन ऑफ बरेली डायोसीज) फादर राजेश (प्रधानाचार्य, सेंट टेरेसा), विद्यालय की प्रबंधिका सिस्टर रिट्टी, प्रधानाचार्या सिस्टर स्मिता मैथ्यू एवं सिस्टर अनीशा सहित प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं नगर के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन की टीम ने कुमाऊँ आयुक्त दीपक रावत को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ हुआ। इसके पश्चात विद्यार्थियों ने उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं दक्षिण भारत की लोकसंस्कृति पर आधारित रंगारंग नृत्य एवं संगीत प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया।



पारंपरिक वेशभूषा, आकर्षक मंच सज्जा और शानदार प्रस्तुतियों ने भारत की सांस्कृतिक विविधता को जीवंत कर दिया।

शहर को स्वच्छ रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी

दीपक रावत ने हल्द्वानी शहर की स्वच्छता पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी एक खूबसूरत शहर है शहर में पेयजल सहित अनेक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन स्वच्छता के प्रति अभी और जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। लोग कूड़ा इधर-उधर न फेंकें और कूड़ेदान का ही उपयोग करें। शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखना हम सभी का सामूहिक कर्तव्य है। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों ने विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रतिभाग की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ ही भारतीय संस्कृति, रचनात्मकता और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्या सिस्टर स्मिता मैथ्यू ने सभी अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया। इस प्रकार वार्षिकोत्सव 'ऐक्य' का भव्य आयोजन इस संदेश के साथ संपन्न हुआ कि दिशाएं भले ही अलग-अलग हों, लेकिन प्रेम, संस्कृति और एकता की भावना हम सभी को एक सूत्र में बांधती है।

नगर आयुक्त आशिमा गोयल ने किया डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण वाहनों का निरीक्षण, व्यवस्था को निर्बाध रखने के दिए निर्देश

के.के.पी संवाददाता

हल्द्वानी। नगर निगम हल्द्वानी की नगर आयुक्त द्वारा शनिवार को नगर क्षेत्र के समस्त 60 वार्डों में संचालित डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण वाहनों की भौतिक एवं परिचालन स्थिति का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त आशिमा गोयल ने ट्रांसपोर्ट नगर, भोलानाथ गार्डन सहित वाहनों के निर्धारित पार्किंग स्थलों पर पहुँचकर वाहनों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान वाहनों की नंबर प्लेट एवं वाहन संख्या की स्पष्ट पठनीयता, बॉडी, टायर, ब्रेक, हॉर्न तथा अन्य आवश्यक उपकरणों की स्थिति की जाँच की गई।

नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि जिन वाहनों में किसी भी प्रकार की मरम्मत अथवा सुधार की आवश्यकता है, उसे समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाए, ताकि सड़कों पर वाहनों के संचालन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो तथा डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था निर्बाध रूप से संचालित होती रहे।निरीक्षण के दौरान समस्त संबंधित वाहन चालकों, सुपरवाइजरों एवं नोडल अधिकारियों को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया था। नगर आयुक्त ने उनसे संवाद कर डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था के संचालन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं एवं आवश्यक सुधारों के संबंध में जानकारी प्राप्त की।



नगर आयुक्त आशिमा गोयल ने कहा कि डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था नगर की स्वच्छता बनाए रखने की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके माध्यम से घरों से नियमित रूप से कूड़ा एकत्रित कर उसका उचित निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है, जिससे नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। इस अवसर पर नगर आयुक्त ने समस्त नगरवासियों से अपील की कि वे अपने घरों में ही गीले एवं सूखे कूड़े को अलग-अलग एकत्रित करें तथा निर्धारित डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण वाहनों में पृथक रूप से उपलब्ध कराएं।

अंतर महाविद्यालयी एथलीट प्रतियोगिता का समापन, टनकपुर महाविद्यालय चैंपियन, मेजबान लोहाघाट उप चैंपियन

छह स्वर्ण पदकों के साथ टनकपुर अव्वल, तीन स्वर्ण जीतकर स्वामी विवेकानंद राजकीय पीजी कॉलेज दूसरे स्थान पर

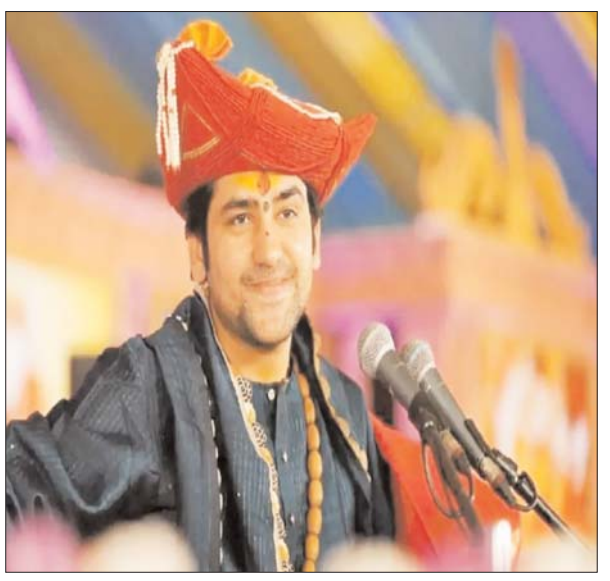
के.के.पी संवाददाता

लोहाघाट। स्वामी विवेकानंद राजकीय पीजी कॉलेज में आयोजित चार दिवसीय अंतर महाविद्यालयी एथलीट प्रतियोगिता का समापन हो गया। आधा दर्जन स्वर्ण पदकों के साथ टनकपुर महाविद्यालय चैंपियन रहा, जबकि तीन स्वर्ण पदकों के साथ मेजबान महाविद्यालय उप चैंपियन घोषित किया गया। प्रतियोगिता में एक दर्जन महाविद्यालयों के साथ चम्पावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ परिसर महाविद्यालय के 61 छात्राओं समेत कुल 129 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



प्राचार्य डॉ. रेखा जोशी ने पुरस्कार वितरित कर चैंपियन और उप चैंपियन टीमों को बधाई दी। उन्होंने सभी महाविद्यालयों के खिलाड़ियों द्वारा खेल के मैदान में उच्च आदर्श और खेल भावना का परिचय देने के लिए उन्हें तथा उनके टीम लीडरों के प्रयासों को सराहा। यह पहला अवसर था, जब छमनियाचौड़ स्टेडियम में महाविद्यालय द्वारा अंतर महाविद्यालयी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें हाफ मैराथन, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो, शॉटपुट और हैमर थ्रो आदि स्पर्धाएं हुईं। क्रीड़ा प्रभारी डॉ. रुचिर जोशी, डॉ. दिनेश राम और विश्वविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी प्रो. लियाकत अली की देखरेख में प्रतियोगिताओं का सफल संचालन हुआ। आयोजन में लता कैड़ा, डॉ. दिनेश व्यास, डॉ. विद्या कुमारी, डॉ. ममता बिष्ट, डॉ. अनीता टम्टा, डॉ. अंजना चंद, डॉ. सुधीर कुमार, डॉ. अनिता खर्कवाल, डॉ. स्वाति कांडपाल, डॉ. सरोज यादव, डॉ. नीरज कांडपाल, डॉ. दीपा सिंह, डॉ. विभा पांडे, डॉ. तनुजा परिहार, डॉ. मीना कुमारी, डॉ. भूप सिंह धामी, डॉ. सरोज पंत, डॉ. ट्विंकल प्रकाश, डॉ. उमा कांडपाल, डॉ. दीपक जोशी, भुवन गिरी, प्रकाश ढेक, रमेश जोशी, कमल किशन, अतुल अधिकारी, एलडी जोशी, रविंद्र कुमार, बृजमोहन जोशी, सुनील राय, विनोद पाटनी और मनोज जोशी के साथ छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु कुमार के नेतृत्व में छात्रसंघ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उल्लेखनीय सहयोग दिया। बाहर से आए महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं और टीम लीडरों ने मेजबान महाविद्यालय की प्राचार्य और उनकी टीम के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय ने अपने नाम के अनुरूप हर क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है, जिसे वे स्मृतियों के रूप में अपने साथ ले जा रहे हैं। डॉ. जोशी ने भी सभी का महाविद्यालय की ओर से आभार प्रकट किया।

कृष्ण भक्तों को लेकर ट्रोलिंग पर बोले बाबा बागेश्वर, कहा- हम बिहारी जी के ही हैं, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे



नई दिल्ली। बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान श्रीकृष्ण को लेकर हुई ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वह ठाकुर बांके बिहारी के भक्त हैं और सनातन धर्म के लिए काम करते रहेंगे. उन्होंने जल्द मंदिर जाकर दर्शन करने की बात भी कही. बाबा बागेश्वर ने कहा कि वह ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे. उन्होंने कहा, 'हम श्रीजी के दर्शन करते रहते हैं. हम बिहारी जी के ही हैं. हम उनकी कथा कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं. हम उन्हीं के हैं.' उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करते हैं. लेकिन जो लोग कुछ दिनों के लिए कृष्ण भक्त बन गए थे, वे अब दिखाई नहीं दे रहे हैं.

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वह सनातन धर्म के लिए लगातार काम करते रहेंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे.

उन्होंने बताया कि कुछ देर में वह ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे. दरअसल, हाल ही में धीरेंद्र शास्त्री ने एक कथा के दौरान भगवान राम और श्रीकृष्ण की तुलना करते हुए श्रीकृष्ण के तीन जगह से टेढ़े होने और बांसुरी बजाने को लेकर टिप्पणी की थी. इस बयान पर संतों और कृष्ण भक्तों ने नाराजगी जताई थी. विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने सफाई देते हुए माफी भी मांगी थी और कहा था कि उनका उद्देश्य भगवान कृष्ण का अपमान करना नहीं था.

जनसुनवाई में आयुक्त दीपक रावत ने मौके पर सुलझाई समस्याएं, भूमि धोखाधड़ी के मामलों में एफआईआर के निर्देश

के.के.पी संवाददाता

हल्द्वानी। आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने कैम्प कार्यालय में भूमि विवाद,एम.एस.एम.ई के तहत सब्सिडी नही देने,बकाया भुगतान कराने,पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा दिलाने, प्लाट में कब्जा दिलाने आदि सम्बन्धित समस्यायें जनसुनवाई में आई अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। भूमि विवाद की छोटी समस्याओं का समाधान तहसील स्तर पर ही हो आयुक्त आयुक्त ने भूमि विवाद से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याओं के उच्चाधिकारियों तक पहुँचने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद की इस प्रकार की छोटी समस्याओं का समाधान उपजिलाधिकारी एवं तहसील स्तर पर ही हो सकता था, लेकिन उनका उच्चाधिकारियों के



कार्यालय तक पहुँचना उचित नहीं है। आयुक्त ने मण्डल के सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसील के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि विवाद की छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान तहसील स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को अनावश्यक रूप से उच्च कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। नैनीताल शहर के अयारपाटा क्षेत्र स्थित प्रयोरी लॉज मामले में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (ईओ) द्वारा बिना विभागीय आख्या एवं मूल नक्शा देखे नक्शा सत्यापित करने पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। वर्तमान अधिशासी अधिकारी द्वारा आयुक्त को अवगत कराया कि मूल अभिलेख प्रयोरी लॉज के कार्यालय में उपलब्ध नही हैं। उन्होंने कहा कि यदि जांच में इस प्रकार का कृत्य सही पाया जाता है, तो संबंधित अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के साथ ही शासन को भी कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाएगा।

बृजेश कुमार को प्लॉट में कब्जा न देने पर भू-स्वामी को 9 लाख वापस करने के निर्देश

ब्रिजेश कुमार ने बताया कि काशीपुर में उन्होंने एक प्लाट 9 लाख रूपये में क्रय किया था प्लाट की रजिस्ट्री के साथ ही दाखिल खारिज भी हो गई। भूस्वामी शमशेर सिंह ने जो भूमि विक्रय की उन्हें गलत खाते में भूमि बेच दी उक्त खाते में भूमि शेष नही होने पर आयुक्त ने भूस्वामी को एक सप्ताह के भीतर अन्यत्र भूमि देने अथवा 9 लाख की धनराशि वापस करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने सम्बन्धित लेखपाल के विरूद्ध भी कार्यवाही के निर्देश दिये।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रानीबाग में ब्लॉक स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन, विद्यार्थियों ने संसदीय संवाद के माध्यम से दिखाई प्रतिभा

के.के.पी संवाददाता

हल्द्वानी/रानीबाग। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रानीबाग में विकासखंड भीमताल की ब्लॉक स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सदस्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग उत्तराखंड योगेश सिंह रजवार की गरिमामयी उपस्थिति रही। प्रतियोगिता में विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों से आए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने प्रतिभाग करते हुए सांसद, मंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका में संसदीय कार्यवाही, समसामयिक विषयों एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में जीजीआईसी भीमताल, जीजीआईसी खुर्पाताल, जीजीआईसी पटुवाडांगर,



जीजीआईसी दोगड़ा एवं जीजीआईसी आमिया के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में जीजीआईसी खुर्पाताल ने प्रथम, जीजीआईसी दोगड़ा ने द्वितीय तथा जीजीआईसी पटुवाडांगर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता विद्यालयों के विद्यार्थियों को मेडल एवं ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सदस्य योगेश सिंह रजवार ने कहा कि युवा संसद जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा, हुनर एवं विचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करती हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों में नेतृत्व क्षमता, तार्किक चिंतन, संवाद कौशल, आत्मविश्वास तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित होती है। जिस आत्मविश्वास, तार्किक क्षमता एवं संसदीय मर्यादा के साथ विद्यार्थियों ने सदन में अपनी बात रखी, वह अत्यंत सराहनीय एवं प्रेरणादायक है। मुख्य अतिथि योगेश सिंह रजवार ने कहा कि उनका निरंतर प्रयास रहेगा कि इस प्रकार की रचनात्मक एवं शैक्षिक प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय स्तर पर लगातार होता रहे, ताकि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के पर्याप्त अवसर मिल सकें और उनका हुनर उच्च मंच तक पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि आगामी 26 नवंबर को जनपद के सभी आठ विकासखंडों की सहभागिता से जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके पश्चात इस प्रतियोगिता को प्रदेश स्तर पर आयोजित कराने के लिए भी उनके द्वारा प्रयास किए जाएंगे, जिससे उत्तराखंड के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का व्यापक अवसर मिल सके।

हल्द्वानी के वैज्ञानिक डॉ. मानस शर्मा ने विकसित किया स्वदेशी क्वांटम सॉफ्टवेयर 'पाइफॉक'

'मेक इन इंडिया' और वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

के.के.पी संवाददाता

हल्द्वानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी से निकले एवं भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बेंगलुरु में कार्यरत, वैज्ञानिक डॉ. मानस शर्मा ने देश के वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

उन्होंने स्वदेशी क्वांटम-केमिस्ट्री सॉफ्टवेयर 'पाइफॉक' विकसित किया है। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला सॉफ्टवेयर पैकेज है, जिसे सरल मानी जाने वाली पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में विकसित किया गया है और जो उच्च गति से जटिल वैज्ञानिक गणनाएं करने में सक्षम है।

यह पहल स्थानीय तकनीक, स्वदेशी क्षमता और वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली 'मेक इन इंडिया' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' की व्यापक भावना से भी जुड़ती है। डॉ. शर्मा ने पाइफॉक के ऊपर, जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो. मारेक सिएरका के साथ शोध-पत्र तैयार किया। यह शोध अमेरिकन केमिकल सोसायटी के एक प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

मानस शर्मा ने बताया, साधारण भाषा में कहें तो पाइफॉक एक प्रकार की डिजिटल वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। यह कंप्यूटर की सहायता से किसी अणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों



की व्यवस्था, उसकी ऊर्जा, स्थिरता और इलेक्ट्रॉनिक गुणों का अनुमान लगाता है। ऐसे गणितीय और कंप्यूटरीकृत प्रयोग नई दवाओं, उत्प्रेरकों, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों और उन्नत रसायनों से संबंधित शोध में वास्तविक प्रयोग करने से पहले वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। डॉ. मानस शर्मा ने जर्मनी के फ्रेडरिक शिलर विश्वविद्यालय येना से भौतिकी में पीएचडी प्राप्त की। उनकी पीएचडी को विश्वविद्यालय के सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान 'सुम्मा कम लॉडे' से सम्मानित किया गया। जर्मनी में उन्होंने विश्व स्तर पर उपयोग किए जाने वाले प्रसिद्ध क्वांटम-केमिस्ट्री सॉफ्टवेयर टर्बोमोल के विकास पर कार्य किया।

विदेश में अपना करियर जारी रखने के बजाय डॉ. शर्मा ने भारत लौटने का निर्णय लिया और अगस्त 2024 में देश के अग्रणी शोध संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु से जुड़े। उनका उद्देश्य भारत में ही उन्नत वैज्ञानिक विधियों और मूलभूत शोध सॉफ्टवेयरों के विकास को बढ़ावा देना है। पाइफॉक को इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।

डॉ. शर्मा की प्रारंभिक शिक्षा निर्मला कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, काठगोदाम-हल्द्वानी में हुई। उनके अनुसार विद्यालय में मिली शिक्षा, अनुशासन और विज्ञान के प्रति प्रोत्साहन ने उनकी भविष्य की उपलब्धियों की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की तथा उच्च शोध के लिए जर्मनी गए। डॉ. मानस की धर्मपत्नी सुश्री प्रियांशी कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग पुणे टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तथा माता सुश्री रश्मि शर्मा वरिष्ठ शिक्षाविद हैं और हल्द्वानी के कई स्कूलों में प्रिंसिपल रह चुकी हैं। वहीं पिता रवि शर्मा वरिष्ठ पत्रकार एवं बाल साहित्यकार हैं।

डॉ. मानस शर्मा की अन्य उपलब्धियां

डॉ. मानस शर्मा के अब तक 13 शोध प्रकाशन प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित शोधपत्र भी शामिल हैं। उनके शोध अमेरिका की अमेरिकन केमिकल सोसायटी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के अलावा फिजिकल रिव्यू बी, एडवांस्ड मैटेरियल्स, नैनो लेटर्स और द जर्नल ऑफ केमिकल फिजिक्स जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं।

डॉ. शर्मा ने भारत, जर्मनी, बेल्जियम और ब्रिटेन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों और प्रतिष्ठित संस्थानों में अपने शोध पर व्याख्यान दिए हैं। इनमें बेल्जियम के विश्वप्रसिद्ध शोध संस्थान आईमेक (द्वद्वद्गष्), ल्यूवेन में आयोजित वैज्ञानिक सम्मेलन तथा ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया गया आमंत्रित व्याख्यान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने जर्मनी के विभिन्न वैज्ञानिक सम्मेलनों और भारत के भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु में भी अपने शोध प्रस्तुत किए हैं।

बैलेट पेपर पर हुए चुनाव में कांग्रेस की धमाकेदार जीत, दिग्गजों के गढ़ में भाजपा का बुरा हाल

जयपुर। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में हुए पंचायत चुनाव के नतीजों ने राज्य की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। कुछ महीने पहले शहरी निकाय चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करने वाली भाजपा को ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस ने करारा झटका दिया है। पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के प्रभाव वाले इलाकों में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ये चुनाव बैलेट पेपर पर हुए थे। जैसा कि कांग्रेस मांग कर रही है कि देश के सभी चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस ने पंचायत समिति की 2,990 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 1,795 सीटें मिलीं। जिला परिषद चुनावों में भी कांग्रेस ने 143 सीटें जीतकर भाजपा को पीछे



छोड़ दिया। भाजपा के खाते में 83 सीटें आईं। इन चुनावों में पूर्व भाजपा सहयोगी हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने भी अपनी ताकत दिखाई। पार्टी ने पंचायत समिति की 438 और जिला परिषद की चार सीटों पर जीत हासिल की। वहीं, निर्दलीय उम्मीदवारों ने पंचायत समिति की 516 सीटें जीतकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भाजपा ने राजस्थान के 301 शहरी निकायों में से 197 में बोर्ड बनाने में कामयाबी हासिल की थी। ऐसे में ग्रामीण और शहरी चुनावों के नतीजों में यह अंतर राज्य की राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है। राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजों की 5 बड़ी बातें।

कांग्रेस पार्टी का यह प्रदर्शन 2020-21 के पंचायत राज चुनावों के नतीजों से बिल्कुल अलग है। उस समय भाजपा ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस पर भारी पड़ी थी। दिसंबर 2020 में 21 जिलों में हुए मुख्य चरण के चुनाव में भाजपा ने जिला परिषद की 636 सीटों में से 353 पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 252 सीटें मिली थीं। जिला परिषद बोर्ड के मामले में भी भाजपा ने 14-15 जिलों में अपना नियंत्रण स्थापित किया था, जबकि कांग्रेस सिर्फ पांच जिलों में बोर्ड बना सकी थी।

पंचायत समिति चुनावों में भी भाजपा ने 1,989 सीटें जीतकर कांग्रेस की 1,852 सीटों के मुकाबले बढ़त बनाई थी। हालांकि, बाद के चरणों में कांग्रेस ने अपनी स्थिति सुधारी थी। जयपुर समेत कुछ इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा था।

जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला टास्क फोर्स की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष जोर

- जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों को स्वास्थ्य मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने के दिए निर्देश
- पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के दिए निर्देश
- जनपद नैनीताल में 22 नवंबर को चलेगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान, 1.21 लाख से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक
- 626 बूथों पर होगा टीकाकरण, घर-घर जाकर भी बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा

के.के.पी संवाददाता

भीमताल। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ललित



मोहन रयाल ने निर्देश दिए कि जनपद के सभी सरकारी एवं निजी चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार, आवश्यक जांच एवं बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। किसी भी गर्भवती महिला की उपचार के अभाव में मृत्यु होने की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रसव पूर्व जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान तथा समय से रेफरल व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया। जिलाधिकारी ने पल्स पोलियो अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक पीने से वंचित न रहे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करें। डॉ. रश्मि पंत द्वारा जनपद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना की जानकारी देते हुए मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, संचारी एवं गैर संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्वास्थ्य गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के सफल संचालन एवं शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं।

जनपद में पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजन के अभियंताओं के स्पष्टीकरण के निर्देश

- जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा,मुख्य चिकित्साधिकारी,मुख्य कृषि अधिकारी,परियोजना निदेशक उरेडा, मुख्य उद्यान अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी का भी स्पष्टीकरण लेने के दिए निर्देश
- जिलाधिकारी ने ओखलकांडा मल्ला रोड निर्माण में विलम्ब की जांच के दिए आदेश, एसडीएम धारी को बनाया जाँच अधिकारी

के.के.पी संवाददाता

भीमताल/नैनीताल। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिला योजना की प्रगति समीक्षा के दौरान 31 अक्टूबर तक शासन द्वारा निर्धारित अपेक्षित न्यूनतम प्रगति 58 प्रतिशत के सापेक्ष बहुत कम प्रगति पर जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा (जिला योजना में 30 प्रतिशत



राशि खर्च, मुख्य चिकित्साधिकारी (जिला योजना में 34 प्रतिशत राशि खर्च), मुख्य कृषि अधिकारी (जिला योजना में 35 प्रतिशत राशि खर्च), परियोजना निदेशक उरेडा (जिला योजना में 45 प्रतिशत राशि खर्च) तथा मुख्य उद्यान अधिकारी (जिला योजना में 55 प्रतिशत राशि खर्च) का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बाल विकास विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया में धीमी प्रगति पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि टेंडर प्रक्रिया अधिप्राप्ति नियमावली के मानकों के अनुसार की गई है तो टेंडर प्रक्रिया रद्द न की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि टेंडर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान पीएमजीएसवाई तीनों डिवीजन द्वारा कुल 22 किमी सड़क निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 2.5 किमी सड़क निर्माण कार्य तथा डी श्रेणी में होने के कारण सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए तीनों डिवीजन ज्योलिकोट, हल्द्वानी, काठगोदाम के अधिशासी अभियंताओं का स्पष्टीकरण लेने तथा संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने निर्माण एजेंसियों के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में जो भी निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं, उनकी टेंडर प्रक्रिया समय से सुनिश्चित करते हुए काम शुरू किए जाएं, यदि आचार संहिता के कारण कार्यों में अनावश्यक विलंब होने पर सम्बन्धितों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

संपादकीय

ट्रंप का भारतीय इकोनॉमी की तारीफ के मायने

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हैं और भारत की करीब सात प्रतिशत विकास दर को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए उदाहरण बताते हैं, तो इसे केवल भारत के प्रति उनके बदले हुए नजरिये के रूप में देखना उचित नहीं होगा। उनकी इस टिप्पणी के पीछे अमेरिकी घरेलू राजनीति, आर्थिक नीतियों और फेडरल रिजर्व के साथ जारी टकराव की पृष्ठभूमि भी है। सवाल यह है कि जिस भारत पर उनके प्रशासन ने टैरिफ संबंधी दबाव बढ़ाया, जिसके नागरिकों के लिए वीजा नीतियां सख्त की गईं, उसी भारत की आर्थिक व्यवस्था अचानक उन्हें इतनी आकर्षक क्यों दिखाई देने लगी? ट्रंप की इस बात में दम है कि भारत में ब्याज दरें कम हैं और जीडीपी सात प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। इसके मुकाबले उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास-दर का जिक्र करते हुए दावा किया कि यदि अमेरिका में भी ब्याज दरें कम रखी जाएं तो विकास दर 14, 15 या 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। उन्होंने अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अच्छे आर्थिक आंकड़े आने के बावजूद केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाने की दिशा में काम करता है। ट्रंप का मानना है कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और सरकारी कर्ज चुकाने की क्षमता मजबूत करने के लिए ब्याज दरें कम होनी चाहिए। दरअसल, ट्रंप और फेडरल रिजर्व के बीच ब्याज दरों को लेकर मतभेद नया नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करे, ताकि कारोबार, निवेश और उपभोग को प्रोत्साहन मिले। दूसरी ओर फेडरल रिजर्व का प्रमुख दायित्व महंगाई को नियंत्रित रखना और रोजगार के स्तर को संतुलित बनाए रखना है। यही वजह है कि वह केवल राष्ट्रपति की इच्छा के अनुरूप ब्याज दरों में बदलाव नहीं कर सकता। मौद्रिक नीति में केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता का उद्देश्य भी यही है कि आर्थिक फैसले राजनीतिक दबाव से प्रभावित न हों।

ट्रंप की टिप्पणी के समय अमेरिका में महंगाई का दबाव भी महत्वपूर्ण है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सितंबर में व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) आधारित महंगाई दर 3.6 प्रतिशत और कोर पीसीई महंगाई दर 3.1 प्रतिशत थी, जबकि फेड का दीर्घकालिक लक्ष्य दो प्रतिशत है। ऐसे में ब्याज दरों में जल्द और बड़ी कटौती महंगाई को फिर बढ़ाने का जोखिम पैदा कर सकती है। इसलिए ट्रंप का यह दावा कि कम ब्याज दरों से अमेरिकी विकास दर सीधे 15 या 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, एक राजनीतिक और आर्थिक अनुमान है, कोई स्थापित आर्थिक निष्कर्ष नहीं। ब्याज दरें विकास को प्रभावित करती हैं, लेकिन उत्पादकता, निवेश, रोजगार, मांग और वैश्विक परिस्थितियां भी इसमें निर्णायक भूमिका निभाती हैं। भारत की तारीफ को भारत-अमेरिका संबंधों के संदर्भ में भी समझना होगा। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में टैरिफ को लेकर तनाव पैदा हुआ। अमेरिकी नीतियों का असर भारतीय निर्यातकों और कारोबारियों की योजनाओं पर पड़ा। वीजा नियमों में सख्ती ने भारतीय पेशेवरों और अमेरिका में काम करने की आकांक्षा रखने वाले युवाओं के सामने भी अनिश्चितता बढ़ाई। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की व्यक्तिगत निकटता और उनकी तारीफ के बयान लगातार चर्चा में रहे हैं। कुछ दिन पहले मोदी को टफ मैन कहना और अब भारतीय अर्थव्यवस्था को उदाहरण बनाना इसी सिलसिले का हिस्सा है। लेकिन कूटनीति में व्यक्तिगत प्रशंसा और नीतिगत सहयोग दो अलग-अलग बातें हैं। नेताओं के बीच मित्रता के सार्वजनिक प्रदर्शन से व्यापारिक बाधाएं अपने आप समाप्त नहीं होतीं। भारत के लिए महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिकी बाजार तक पहुंच, निर्यात पर शुल्क, तकनीकी सहयोग, निवेश और भारतीय पेशेवरों के वीजा जैसे मुद्दों पर ठोस प्रगति हो। इसी तरह अमेरिका के लिए भारत एक बड़ा बाजार, निवेश का अवसर और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में महत्वपूर्ण भागीदार है। दोनों देशों के आर्थिक हित एक-दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए आपसी मतभेदों का असर केवल सरकारों तक सीमित नहीं रहता।

विदेश की धरती से भारत की कमियां गिनाने के बजाय राहुल गांधी देश को बताएं समाधान का रास्ता

कांतिलाल मांडोत

केवल आरोपों से नहीं जीता जाता मतदाताओं का विश्वास कांग्रेस को भी राहुल के बयानों पर आत्ममंथन करना चाहिए

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, जनता की समस्याओं को सामने लाना और सत्ता को जवाबदेह बनाना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन विपक्ष की राजनीति केवल आलोचना और आरोपों तक सीमित रह जाए तो जनता के मन में स्वाभाविक रूप से सवाल उठने लगते हैं। देश को केवल यह बताने से काम नहीं चलेगा कि समस्याएं कितनी हैं, बल्कि यह भी बताना होगा कि उनका समाधान कैसे होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने भारत में बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि देश के युवाओं को भविष्य की चिंता सता रही है और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर सवाल हैं। इन मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि बेरोजगारी और चुनावी निष्पक्षता लोकतंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की समस्याओं को विदेश में गिनाने से उनका समाधान निकल आएगा? क्या राहुल गांधी के पास इन समस्याओं को दूर करने की कोई ठोस योजना भी है?

पिछले ग्यारह वर्षों में राहुल गांधी कई बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। अलग-अलग अवसरों पर उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी, महंगाई, कश्मीर, लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर अपनी बात रखी है। लोकतंत्र में किसी भी नेता को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन जब कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता विदेश में भारत की व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाता है तो उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह देश की उपलब्धियों और संभावनाओं को भी सामने रखे। भारत केवल समस्याओं से घिरा देश नहीं है। यहां विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, सड़क, रेल और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। भारतीय युवा दुनिया के अनेक देशों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। इन उपलब्धियों को स्वीकार करना किसी सरकार का समर्थन करना नहीं, बल्कि देश की प्रगति को पहचानना है।

राहुल गांधी बेरोजगारी की बात करते हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कांग्रेस के पास इसका क्या समाधान है। युवाओं को रोजगार चाहिए, केवल भाषण नहीं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, कौशल विकास, उद्योगों का विस्तार और छोटे कारोबार को प्रोत्साहन देना समय की आवश्यकता है। सरकार से रोजगार के आंकड़ों और रिक्त पदों पर सवाल पूछना उचित है, लेकिन विपक्ष को भी अपनी रोजगार नीति जनता के सामने रखनी चाहिए। कांग्रेस यह बताए कि सत्ता में आने पर वह कितने रोजगार के अवसर पैदा करेगी और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाएगी।

भारत को मिलेगी बुलेट ट्रेन की उड़ान, विकास के नए युग का होगा सूत्रपात

विनोद सिंह 'तकियावाला'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना ले रही है आकार; रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के विजन, जापानी तकनीक और भारतीय इंजीनियरों के कौशल से विकसित हो रहा देश का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, 2027 में पहली सेवा शुरू करने का लक्ष्य

भारत की विकास यात्रा में कुछ परियोजनाएँ केवल परिवहन का माध्यम नहीं बनतीं, बल्कि वे देश की तकनीकी क्षमता, आर्थिक महत्वाकांक्षा और भविष्य की दिशा का प्रतीक बन जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना ऐसी ही एक ऐतिहासिक पहल है। देश में पहली बार बुलेट ट्रेन का सपना अब धरातल पर आकार ले रहा है। यह परियोजना केवल मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग, औद्योगिक विकास, रोजगार, पर्यटन, निवेश और आत्मनिर्भर भारत की संभावनाओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास है।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 अक्टूबर 2026 को अपने विस्तृत आलेख 'इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन इज टेकिंग शेप' में इस परियोजना की प्रगति, तकनीकी विशेषताओं और भविष्य की योजनाओं का उल्लेख किया है। उनके प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट है कि भारत का पहला हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर अब केवल घोषणा नहीं, बल्कि विशाल निर्माण कार्य, आधुनिक तकनीक और भारतीय श्रम-कौशल के समन्वय से वास्तविकता बन रहा है। प्रधानमंत्री की विकास परिकल्पना को आगे बढ़ाने में रेल मंत्री का तकनीकी दृष्टिकोण और परियोजना के क्रियान्वयन की गति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

दो महानगर नहीं, एक व्यापक आर्थिक क्षेत्र

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 508 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, गुजरात और केंद्रशासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली से होकर गुजरेगा। मार्ग पर मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती सहित 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी गति है। ट्रेन की डिजाइन गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा और परिचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा लगभग एक घंटा 58 मिनट में पूरी करने की परिकल्पना है, जबकि सड़क मार्ग से इस दूरी को तय करने में सामान्यतः आठ से नौ घंटे लग जाते हैं।

इस बदलाव का वास्तविक महत्व समय की बचत से कहीं आगे है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, जबकि अहमदाबाद और गुजरात का औद्योगिक क्षेत्र व्यापार, वस्त्र, हीरा, रसायन और विनिर्माण गतिविधियों का बड़ा केंद्र है। इनके बीच तेज और विश्वसनीय संपर्क से कारोबारी यात्राएँ आसान होंगी। सूरत, वडोदरा, आणंद और ठाणे जैसे शहरों को भी इसका लाभ मिलेगा। विद्यार्थी, पेशेवर, उद्यमी और पर्यटक कम समय में लंबी दूरी तय कर सकेंगे। इससे विभिन्न शहरों के बीच रोजगार, निवेश और व्यावसायिक अवसरों का विस्तार हो सकता है। जापान की हाई-स्पीड रेल व्यवस्था का अनुभव भी यही बताता है कि तेज रेल संपर्क अलग-अलग शहरों की अर्थव्यवस्थाओं को एक-दूसरे के निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

आसमान में दौड़ता आधुनिक रेल कॉरिडोर

इस परियोजना का लगभग 465 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड वायाडक्ट पर बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य रेल मार्ग को सामान्य सड़क यातायात, समपार फाटकों, पशुओं और अनधिकृत आवाजाही से अलग रखना है। इससे ट्रेन को उच्च गति से सुरक्षित परिचालन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेंगी। रेल मंत्री के अनुसार, सितंबर 2026 तक 456 किलोमीटर पियर निर्माण और 371 किलोमीटर वायाडक्ट निर्माण पूरा हो चुका था। लगभग 299 किलोमीटर हिस्से में छह लाख से अधिक शोर अवरोधक लगाए गए थे। वहीं, 206 किलोमीटर वायाडक्ट पर 9,300 से अधिक ओवरहेड विद्युतीकरण मस्तूल स्थापित किए जा चुके थे।चार पर्वतीय सुरंगों की खुदाई भी पूरी हो चुकी थी। परियोजना के आठ स्टेशनों पर सिविल निर्माण कार्य पूरा होने के बाद वास्तुशिल्प संबंधी अंतिम कार्य आगे बढ़ रहा था। ये उपलब्धियाँ इस विशाल परियोजना के निर्माण की व्यापकता और तकनीकी जटिलता को दर्शाती हैं।

समुद्र के नीचे सुरंग, इंजीनियरिंग का असाधारण उदाहरण

इस परियोजना का सबसे चुनौतीपूर्ण और आकर्षक हिस्सा महाराष्ट्र में बनने वाली लगभग 21 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग है। इसमें करीब सात किलोमीटर का हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे समुद्र के भीतर से गुजरेगा। यह भारत की पहली समुद्र के नीचे बनने वाली रेल सुरंग होगी। इसके निर्माण में अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रत्येक मशीन का कटरहेड 13.6 मीटर व्यास का है और मशीन का वजन तीन हजार टन से अधिक है। जुलाई 2026 में इन विशाल मशीनों को निर्माण कार्य में लगाया गया। इनके माध्यम से कठोर चट्टानों को काटकर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है।

मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में लगभग 32 मीटर जमीन के नीचे एक भूमिगत स्टेशन भी विकसित किया जा रहा है। यह करीब दस मंजिला इमारत की गहराई के बराबर है। घनी आबादी वाले व्यावसायिक क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के सहारे इतने विशाल स्टेशन का निर्माण भारतीय इंजीनियरिंग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यहां प्लेटफॉर्म, यात्री सुविधाओं और तकनीकी सेवाओं के लिए अलग-अलग स्तर बनाए जा रहे हैं।

जापानी तकनीक और भारतीय आत्मनिर्भरता का संगम

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत और जापान के तकनीकी सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसकी आधारशिला रखी थी। जापान की शिंकानसेन तकनीक और वित्तीय सहयोग से शुरू हुई इस परियोजना में अब भारतीय इंजीनियरों, तकनीशियनों और निर्माण कंपनियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड है। इसके अंतर्गत लगभग 40 मीटर लंबा और 970 टन वजनी कंक्रीट गर्डर कारखाने में तैयार किया जाता है और विशेष मशीनों की सहायता से निर्धारित स्थान पर स्थापित किया जाता है। इससे निर्माण की गति और गुणवत्ता दोनों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

शुरुआती चरण में आयात की गई भारी मशीनों के डिजाइन और निर्माण में भी भारतीय इंजीनियरों ने अपनी क्षमता विकसित की है। आज एक हजार टन से अधिक भार उठाने वाली विशाल निर्माण मशीनों का स्वदेश में डिजाइन और निर्माण किया जा रहा है।

इसी तरह भारतीय रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्टरी और बीईएमएल के सहयोग से स्वदेशी हाई-स्पीड ट्रेनसेट विकसित किए जा रहे हैं। बी-28 ट्रेनसेट का पहला बॉडी फ्रेम तैयार हो चुका है और उसका संरचनात्मक परीक्षण चल रहा है। इसकी डिजाइन गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इसके बाद 350 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति वाले बी-35 ट्रेनसेट की दिशा में आगे बढ़ने की योजना है। हाई-स्पीड रेल के लिए आवश्यक ट्रैक, विद्युतीकरण और अन्य तकनीकी उपकरणों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना भी इसी प्रयास का हिस्सा है। इसका दीर्घकालिक लाभ यह होगा कि भारत केवल विदेशी तकनीक का उपयोग करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि उसके निर्माण, रखरखाव और विकास में भी अपनी क्षमता स्थापित कर सकेगा।

सुरक्षा और विद्युतीकरण की अत्याधुनिक व्यवस्था

320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन के लिए सामान्य रेल व्यवस्था से कहीं अधिक उन्नत सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है। इस कॉरिडोर में 28 भूकंपीय सेंसर लगाने की योजना है। भूकंप की प्राथमिक तरंगों का पता लगते ही बिजली आपूर्ति बंद करने और ट्रेन को सुरक्षित रूप से रोकने की स्वचालित व्यवस्था विकसित की जा रही है।

प्रजातंत्र की रक्षा, फासीवाद से मुकाबला समय की जरूरत

राम पुनियानी

भारत शिखर सम्मेलन 2026 के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए जाने और राजनेताओं और बड़े कारोबारी घरानों के बीच सांठगांठ की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत में 2014 से फासीवादियों का शासन शुरू हुआ और तभी से भारत में प्रजातंत्र खतरे में है। देश में इन दिनों एसआईआर के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चल रहा है। नागरिकों ने अपने समूह गठित किए हैं और वे लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसके चलते करोड़ों लोगों को वोट देने के अपने हक से महरूम होना पड़ा है।

वी-डेम इन्स्टीट्यूट के इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन्डेक्स (चुनावी प्रजातंत्र सूचकांक) में दुनिया के 179 देशों में से भारत 106वें स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत का स्कोर 0.38 है जो कि 1975 में लगे आपातकाल के बाद से सबसे कम है। इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत एक पूर्ण प्रजातंत्र के स्थान पर निर्वाचित तानाशाही बन गया है। एसआईआर और अन्य मुद्दों पर चलाए जा रहे आन्दोलनों को सरकार ने बहुत सख्ती से कुचला है। इन आन्दोलनों में शामिल लोगों की बुरी तरह पिटाई की गई। यह इस तथ्य के बावजूद कि वे लोग पूरी तरह अहिंसक थे। हमारे वर्तमान शासक मतदाता सूचियों से अपने विरोधियों के नाम गायब कर देना चाहते हैं ताकि भले ही उनकी लोकप्रियता कितनी ही कम हो जाए, वे चुनावों में जीत हासिल करते रहें।

इसके पहले भाजपा ने असम में एनआरसी के जरिए लोगों के वोट देने के हक को छीनने का प्रयास किया था। मगर उनके दावों के विपरीत असम में जिन 20 लाख लोगों के पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं थे, उनमें से 12 लाख हिन्दू थे। भाजपा और उसकी सरकारें और नेता चिल्ला-चिल्लाकर कहते आ रहे हैं कि भारत में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिये रह रहे हैं। मगर तथ्य उनके दावों से मेल नहीं खाते। भारत के सत्ताधारी दल ने पहले ही न्यायपालिका में घुसपैठ बना ली है। न्यायपालिका पर उसका गहरा प्रभाव है। उसने अनेक स्वायत्त संस्थाओं को भी अपनी कठपुतली बना लिया है और वह हर तरह से लोगों के प्रजातांत्रिक हकों को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में राहुल द्वारा उन्हें फासीवादी कहना गलत नज़र नहीं आता।

आरएसएस के जन्मदाता समाज के वे वर्ग थे जो अंग्रेजों के राज के समय शुरू हुए प्रजातंत्र-समर्थक आंदोलनों के खिलाफ थे। वे लोग सामन्त, जमींदार और पुरोहित वर्ग के थे जो सामंतीकाल के ऊँच-नीच के मूल्यों को बनाए रखना चाहते थे। ये लोग न केवल ब्रिटिश-विरोधी संघर्ष से दूर रहे वरन उन्होंने सामाजिक-प्रजातांत्रिक सुधार आंदोलनों का भी विरोध किया। वे नहीं चाहते थे कि श्रमिकों को यूनियन बनाने का हक मिले, वे नहीं चाहते थे कि दलित और महिलाएं शिक्षा हासिल कर सकें। राष्ट्रीय आन्दोलन को दिशा देने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महती भूमिका थी जिसने देश को स्वाधीन और प्रजातांत्रिक बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। एक ओर मुस्लिम लीग और दूसरी ओर आरएसएस-हिन्दू महासभा अपने-अपने धर्मों के नाम पर अलग राष्ट्रों की मांग कर रहे थे। आगे चलकर आरएसएस ने भारतीय संविधान और हमारे तिरंगे झंडे का विरोध किया, मनुस्मृति के मूल्यों को सही ठहराया और भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूल्यों की खिलाफत की।

वे फासिज्म पर मुग्ध थे और उन्होंने फासिज्म के मूल्यों और उसके काम करने के तरीकों की खुलकर प्रशंसा की। हिन्दू महासभा के डॉ. बी.एस. मुन्जे, मुसोलिनी से खासे प्रभावित थे। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन से वापिस लौटते हुए उन्होंने इटली में रूककर मुसोलिनी से मुलाकात की। वे इटली के फासीवादी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग बालील्ला से भी काफी प्रभावित थे। अपनी पुस्तक 'शेडो ऑफ स्वास्तिक' (स्वास्तिक की छाया) में मर्जिया केसारोली ने इस मुलाकात का विस्तार से विवरण दिया है। किताब का उपशीर्षक है ''भारतीय उग्र राष्ट्रवाद, इतालवी फासीवाद और नाज़ीवाद के परस्पर रिश्ते''। इसी तरह आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक एमएस गोलवलकर ने अपनी पुस्तक ''व्ही ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड'' में जर्मनी के नाज़ीवाद की शान में कसीदे काढ़े हैं। वे लिखते हैं, ''...अपने राष्ट्र और संस्कृति की शुद्धता बनाए रखने के लिए जर्मनी ने देश को यहूदियों से मुक्त कर पूरी दुनिया को चैंका दिया। यह राष्ट्रगौरव की उच्चतम अभिव्यक्ति है। जर्मनी ने यह भी दिखाया है कि जिन नस्लों और संस्कृतियों में मूलभूत फर्क होते हैं वे कभी एक नहीं हो सकतीं। यह हिन्दुस्तान में हम लोगों के लिए एक सबक है जिसे हम सीख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं (व्ही ऑर अवर नेशनहुड डिफाइन्ड, पृष्ठ 27, नागपुर, 1938)। गोलवलकर ने ही हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीति के दो मूल सिद्धांतों की स्थापना की थी जो आज की भाजपा की राजनीति का आधार हैं। पहला, उन्होंने मुसलमानों, ईसाईयों और कम्युनिस्टों को देश का आंतरिक शत्रु बताया और दूसरा उन्होंने मनुस्मृति और उसमें निहित जातिगत और लैंगिक ऊँच-नीच का महिमामंडन किया। सन 2014 के आमचुनाव में मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। उनकी छवि को चमकाने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियों और एजेन्सियों की मदद ली गई। प्रधानमंत्री बनने के पहले ही उनके आसपास एक आभामंडल निर्मित कर दिया गया। समाजविज्ञानी आशीष नंदी ने मोदी का एक इंटरव्यू लिया था जिसके बाद नंदी इस नतीजे पर पहुंचे थे कि मोदी एक खालिस फासीवादी हैं। फासीवादी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपशब्द के रूप में नहीं बल्कि एक रोग की पहचान के रूप में किया था। नंदी लिखते हैं, ''करीब एक दशक पहले जब नरेन्द्र मोदी कुछ भी नहीं थे, वे एक छोटे-मोटे आरएसएस प्रचारक थे जो भाजपा में कोई पद हासिल करना चाहता था, उस समय मुझे उनका साक्षात्कार लेने का सौभाग्य मिला था। साक्षात्कार के बाद मेरे मन में कोई संदेह नहीं बचा कि वे एक खालिस, क्लिनीकल फासिस्ट हैं। मैं 'फासिस्ट' शब्द का इस्तेमाल एक गाली के रूप में नहीं करता।

मेरे लिए वह एक रोग है जिसमें संबंधित व्यक्ति की विचारधारा और उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं के अलावा यह भी शामिल होता है कि उसका प्रेरणास्त्रोत कौन या क्या है।

जेलें मनुष्य को फिर से मनुष्य बनाने के केन्द्र बने

ललित गर्ग

किसी भी सभ्य समाज की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि वह अपराधियों को कितनी कठोर सजा देता है, बल्कि इससे होती है कि वह अपराध करने वाले मनुष्य को सुधारने के कितने अवसर देता है। अपराध की गंभीरता को कम करना न्याय नहीं है, लेकिन अपराधी को हमेशा अपराध की पहचान से बांध देना भी न्याय की पूर्ण अवधारणा नहीं हो सकती। सजा आवश्यक है, किंतु सजा का अंतिम उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, सुधार, नवनिर्माण और समाज की सुरक्षा होना चाहिए। इसी मानवीय दृष्टि से अब समय आ गया है कि भारत की जेल व्यवस्था को एक नई सोच, नई भाषा और नई कार्यप्रणाली दी जाए। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की सभी जेलों में 'बोर्ड ऑफ विजिटर्स' गठित करने का निर्णय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जेलों की आंतरिक व्यवस्था, बंदियों की समस्याओं, स्वास्थ्य, रहन-सहन, पुनर्वास तथा अधिकारों की निगरानी के लिए स्वतंत्र और संवेदनशील व्यवस्था बनाना निश्चित रूप से स्वागतयोग्य पहल है। बहुत जरूरत है कि दंड से सुधार, अपराधबोध से आत्मबोध और कारावास से पुनर्वास की ओर बढ़े भारतीय जेल व्यवस्था। पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि वह अपराधियों को कितनी कठोर सजा देता है, बल्कि इससे होती है कि वह अपराध करने वाले मनुष्य को सुधारने के कितने अवसर देता है। अपराध की गंभीरता को कम करना न्याय नहीं है, लेकिन अपराधी को हमेशा अपराध की पहचान से बांध देना भी न्याय की पूर्ण अवधारणा नहीं हो सकती। सजा आवश्यक है, किंतु सजा का अंतिम उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, सुधार, नवनिर्माण और समाज की सुरक्षा होना चाहिए। इसी मानवीय दृष्टि से अब समय आ गया है कि भारत की जेल व्यवस्था को एक नई सोच, नई भाषा और नई कार्यप्रणाली दी जाए। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की सभी जेलों में 'बोर्ड ऑफ विजिटर्स' गठित करने का निर्णय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जेलों की आंतरिक व्यवस्था, बंदियों की समस्याओं, स्वास्थ्य, रहन-सहन, पुनर्वास तथा अधिकारों की निगरानी के लिए स्वतंत्र और संवेदनशील व्यवस्था बनाना निश्चित रूप से स्वागतयोग्य पहल है। बहुत जरूरत है कि दंड से इसे केवल किसी न्यायिक निर्देश की अनुपालना मानकर सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जेल सुधार की व्यापक राष्ट्रीय नीति का प्रारंभिक बिंदु बनाया जाना चाहिए।

जेल शब्द ही हमारी मानसिकता का दर्पण है। 'जेल' सुनते ही हमारे मन में बंद दीवारें, सलाखें, अपराध, सजा और भय की तस्वीर उभरती है। क्या हम इस संस्थान को ऐसी भाषा दे सकते हैं, जो सुधार की संभावना को सामने रखे? 'सुधारगृह', 'पुनर्वास केंद्र', 'मानव पुनर्निर्माण केंद्र', 'नवजीवन केंद्र' अथवा 'मानव सुधार एवं पुनर्वास गृह' जैसे नामों पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। नाम बदलना मात्र प्रतीकात्मक कार्य नहीं होगा, यदि उसके साथ कार्यसंस्कृति भी बदले। दीवारों पर लिखे शब्द बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था तब बदलती है जब उसके पीछे की सोच बदलती है। भारत की जेल व्यवस्था आज अनेक चुनौतियों से घिरी है। क्षमता से अधिक बंदी, बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी, कर्मचारियों की कमी, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अपर्याप्त पुनर्वास व्यवस्था तथा कभी-कभी भेदभाव और दुर्व्यवहार की शिकायतें यह बताती हैं कि केवल कारागार भवनों का विस्तार पर्याप्त नहीं है। हमें 'अपराध प्रबंधन' से आगे बढ़कर 'मानव पुनर्निर्माण' की व्यवस्था विकसित करनी होगी।

जेल में बंद व्यक्ति अपराध कर सकता है, लेकिन वह केवल अपराध नहीं है। उसके भीतर एक मनुष्य भी है-जिसमें विचार बदलने, पश्चात्ताप करने, सीखने और नया जीवन शुरू करने की क्षमता हो सकती है। न्याय व्यवस्था उसके अपराध का निर्धारण करती है, लेकिन सुधार व्यवस्था उसके भविष्य की संभावना तलाश सकती है। इसलिए जेल प्रशासन को सुरक्षा और अनुशासन के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सक्रिय होना चाहिए। यहीं से 'सुधारगृह' की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रत्येक जेल में अच्छी पुस्तकालय व्यवस्था हो, नियमित खेलकूद हों, योग और ध्यान की गतिविधियां हों, प्रेरक व्याख्यान हों, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण हो, संगीत, कला, लेखन और हस्तशिल्प जैसी रचनात्मक गतिविधियां हों। कैदियों के लिए व्यक्तित्व विकास, क्रोध-प्रबंधन, नशामुक्ति, पारिवारिक संबंध, नैतिक शिक्षा और जीवन-कौशल की कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। उन्हें केवल यह न बताया जाए कि उन्होंने क्या गलत किया, बल्कि यह भी सिखाया जाए कि अब उन्हें सही दिशा में कैसे आगे बढ़ना है।

इस संदर्भ में भारत के अणुव्रत आंदोलन का अनुभव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आचार्य तुलसी के नेतृत्व में अणुव्रत आंदोलन ने प्रारंभ से ही व्यक्ति के भीतर नैतिक चेतना जगाने को परिवर्तन का आधार माना। जेलों में भी अणुव्रत के माध्यम से नैतिक जागरण, आत्मचिंतन, ज्ञान और जीवन-मूल्यों से जुड़े कार्यक्रम चलाए गए। इसका मूल संदेश था कि मनुष्य को केवल उसके अतीत से नहीं, उसके परिवर्तन की संभावना से भी देखा जाना चाहिए। यह अनुभव आज की जेल सुधार नीति के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा बन सकता है। अपराध से लड़ने का एक रास्ता कठोरता है, लेकिन उससे अधिक स्थायी रास्ता चेतना का परिवर्तन है। जिस व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने, किसी विद्वान को सुनने, ध्यान करने, योग सीखने, कोई हुनर विकसित करने और अपने जीवन पर विचार करने का अवसर मिलता है, उसके भीतर परिवर्तन के द्वार खुल सकते हैं। जेल में बंद व्यक्ति को समाज से काटकर रखना आवश्यक हो सकता है, लेकिन उसे मानवीय समाज से पूरी तरह विमुख कर देना आवश्यक नहीं है।

'बोर्ड ऑफ विजिटर्स' की नई व्यवस्था को भी इसी व्यापक दृष्टि से जोड़ा जाना चाहिए। बोर्ड केवल निरीक्षण करने वाला निकाय न हो, बल्कि जेल सुधार का संवेदनशील प्रहरी बने। वह बंदियों से सीधे संवाद करे, उनकी शिकायतें सुने, स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति देखे, कानूनी सहायता की उपलब्धता जांचे और पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करे। उसकी रिपोर्टों के आधार पर समयबद्ध सुधार सुनिश्चित किए जाएं। यदि संभव हो तो नागरिक समाज, शिक्षा, मनोविज्ञान, चिकित्सा, विधि, खेल, योग, आध्यात्म और सामाजिक सेवा से जुड़े विशेषज्ञों को भी इस प्रक्रिया से जोड़ा जाए। साथ



कितने तरह की स्केटिंग

रोलर स्केटिंग, आइस स्केटिंग, इन लेन स्केटिंग। रोलर स्केटिंग का भारत में बहुत चलन है। इसे सीखना आसान है।

स्केटिंग करो फिट रहो

स्केटिंग उतनी ही आसान और सुरक्षित है जितना कि दूसरे गेम खेलना, जैसे साइकिल चलाना, बास्केटबॉल या अन्य गेम खेलना। आजकल बहुत से स्कूलों में स्केटिंग सिखाई जाती है। स्केटिंग केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं है, बल्कि तुम इसे अपना कॅरियर भी बना सकते हो। स्केटिंग के भारत में बहुत से प्रक्षिशण केंद्र हैं, जो बच्चों को चुनकर उन्हें दूसरे देशों में चैम्पियनशिप के लिए भेजते हैं। लेकिन ये सब बातें करने से पहले यह जानो कि स्केटिंग के क्या फायदे हैं –



स्केटिंग एक ऐसी व्यायाम की मशीन है, जिसको करने से तुमको मजा भी आता है और चुस्त और स्वस्थ रहते हो। पैरों की ताकत बढ़ती है। शरीर की सभी मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। रीढ़ की हड्डी भी सही रहती है।

हाथों और पैरों का सामंजस्य बनाए रखने में मदद मिलती है। दिमाग और समझने की क्षमता बढ़ती है। चौकन्ना रहकर सीखते हो।

स्केटिंग करना भागना और साइकिल चलाने से अधिक फायदेमंद है। तुमको सब बच्चों से मिलने का और बात करने का मौका मिलता है और नई जानकारी मिलती है।



शंख मछली पर निर्भर विशालकाय वालरस

उत्तरी गोलार्द्ध में पाया जाने वाला तथा उथले पानी में रहने वाला 'वालरस' एक विशालकाय जानवर है जिसकी लंबाई करीब 13 फुट तथा वजन करीब 2 टन होता है। इनके टस्क (खांग) की लंबाई करीब 3 फुट होती है। वालरस इन टस्क का प्रयोग प्राय: बर्फ को खोदने के लिए करते हैं, ताकि ये अपने शरीर को पानी से बाहर निकाल सकें। मादा वालरस करीब सवा साल के गर्भाधान के बाद एक शिशु को जन्म देती है और करीब 3 साल तक उसकी देखभाल करती है। वालरस भोजन के लिए प्राय: शंख मछली पर ही निर्भर रहते हैं। वालरस के लंबे टस्क प्राप्त करने के लिए शिकारी इनका बड़ी तादाद में शिकार करते हैं, जो काफी महंगे बिकते हैं। वैसे वालरस का शिकार इसके मांस, इसके शरीर से प्राप्त चमड़े तथा तेल के लिए भी किया जाता है। यही कारण है कि वालरस नामक यह विशालकाय जानवर भी अब लुप्त होते प्राणियों की श्रेणी में शुमार है।



वृहस्पति का नया चंद्रमा!

दोस्तों, तुम्हें तो पता ही होगा कि वृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। अब ताजा खबर यह है कि वैज्ञानिकों ने इसका एक और नया उपग्रह खोज निकालने का दावा किया है। इसे वृहस्पति का 17वां उपग्रह माना जा रहा है। दरअसल, पिछले साल अरीजोना यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स के वैज्ञानिकों ने वृहस्पति के चारों ओर एक आकृति को चक्कर काटते देखा था। फिर स्पेसवॉच कार्यक्रम के तहत धूमकेतुओं और क्षुद्रग्रहों को स्कैन कर दिया गया। जब उन्होंने इस नए उपग्रह को देखा तो उन्हें लगा कि यह या तो कोई क्षुद्रग्रह है या कोई धूमकेतु।

(क्षुद्रग्रह बर्फ और धुएं का छोटा सा हिस्सा होता है और सूर्य के चारों तरफ घूमता रहता है। जब यह सूर्य के पास पहुंचता है तो यह धूमकेतु वाष्पीकृत होकर सिर और पूंछ में तब्दील हो जाता है। सौर मंडल में क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं।)

वैज्ञानिकों ने इस बात पर विचार किया कि जो यह नई चीज दिखाई दे रही है, वह अगर क्षुद्रग्रह और धूमकेतु नहीं है तो आखिर क्या है? वैज्ञानिक इस बात को लेकर बड़ी उलझन में थे। वे सोच रहे थे कि हमने जो पिछले महीने ऑर्बिट में देखा था, वह आखिर क्या था? (सौर मंडल में ऑर्बिट एक ऐसा रास्ता है, जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु के चारों ओर घूमती है। ऑर्बिट में हर चीज अपने आप में खास होती है।) वैज्ञानिकों ने पाया कि वृहस्पति ग्रह के चारों ओर घूमने वाला यह नया उपग्रह है, जो पहले नहीं देखा जा सका था। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने इस उपग्रह के लिए कोई खास नाम नहीं रखा है। फिलहाल इसे एस/1999 जे नाम से पुकारा जा रहा है।

नए पाए गए उपग्रह का व्यास 5 किमी है। इसका मतलब यह है कि इस उपग्रह के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलने में केवल 5 किमी का सफर करना होगा। इस तरह देखा जाए तो यह वृहस्पति ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह है। केवल वृहस्पति का ही नहीं, बल्कि इस सौर मंडल का यह सबसे छोटा उपग्रह होगा। इस उपग्रह के पाए जाने से पहले वृहस्पति का जो सबसे छोटा उपग्रह था, उसका नाम लेडा था। लेडा का व्यास 8 से 16 किमी तक था। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यह देखोगे कि इससे पहले भी वृहस्पति के उपग्रहों में हलचल दिखाई दी है। कुछ दिनों पहले वृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह भी खोजा गया था। सबसे बड़े उपग्रह ने बहुत हलचल मचाई। यह उपग्रह हमारे सौर मंडल में पाया जाने वाला अकेला उपग्रह है, जहां धरती की तुलना में ज्वालामुखी गुण कहीं ज्यादा पाए जाते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि यह वृहस्पति का आखिरी उपग्रह नहीं है। यह उपग्रह अपने अंदर बहुत से रहस्य समेटे हुए है, जो वक्त के साथ खोजने पर सामने आएंगे।

हमारा चांद सबसे अनूठा

हमारे पास यानी पृथ्वी के पास एक ही चांद है, जिसे हम चंदा मामा कहते हैं। अपने सौरमंडल का सबसे चमकीला है अपना चंद्रमा। तुम्हें तो मालूम ही है कि हमारे और सूर्य के बीच में दो और ग्रह हैं। सूर्य के सबसे करीब बुध है और दूसरे स्थान पर शुक्र। हम तीसरे स्थान पर हैं। बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है, लेकिन हमारे पास एक चंद्रमा है। उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और वह चमकता रहता है। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि हम कभी भी पूरे चांद को नहीं देख पाते। हमेशा उसका एक ही हिस्सा हम देख पाते हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जितने समय में वह हमारी पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, उतने ही समय में अपनी धुरी पर भी एक चक्कर लगा लेता है। इस कारण हमें उसका एक ही हिस्सा दिखता है और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का समय लग जाता है। यह हमारी पृथ्वी से काफी करीब भी है। पृथ्वी से इसकी औसत दूरी लगभग 3 लाख 84 हजार 400 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कभी कम और कभी अधिक हो जाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, उस समय यह दूरी लगभग 4 लाख 5 हजार 500 किलोमीटर होती है और जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ जाता है तो दोनों के बीच की दूरी 3 लाख 56 हजार 300 किलोमीटर हो जाती है। शायद तुम्हें यह मालूम नहीं होगा कि समुद्र में बड़ी-बड़ी लहरें कब और क्यों उठती हैं। यह अपने चंद्रमा के कारण ही होता है। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है तो समुद्र में ऐसी लहरें उठती हैं। इसका कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। वैसे तो यह बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के छठे हिस्से के बराबर है, लेकिन समुद्र के पानी पर उसका असर हो ही जाता है। अगर तुम वहां जाना चाहो तो रॉकेट से सिर्फ 13 घंटे में पहुंच सकते हैं। प्रकाश को तो इतनी दूरी तय करने में दो सेकेंड भी नहीं लगते हैं। चंद्रमा का व्यास 3476 किलोमीटर है। अगर तुम ऐसे चार चंद्रमाओं को मिला दोगे तो जितना बड़ा चंद्रमा बनेगा, उतनी ही बड़ी है हमारी पृथ्वी। यानी हमारी पृथ्वी का लगभग एक चौथाई आकार है चंद्रमा का। यहां न तो हवा है और न ही मौसम। वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगा लिया है कि पृथ्वी की एक बड़ी टक्कर से चंद्रमा बना। यह टक्कर आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी।

भोलू बना सितारा

भोलू, नमन, दिव्या और आंचल जगदंबा बस्ती में रहते थे। नमन और दिव्या को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। भोलू को ड्रामा पसंद था और आंचल को डांस करना अच्छा लगता था। सभी की उम्र 10 से 12 साल थी। इन दिनों चारों बच्चे अपने ही स्कूल में ड्रामा सीख रहे थे। ड्रामा, कला अकादमी के सौजन्य से किया जा रहा था। कला अकादमी ने निर्धन वर्ग के बच्चों की प्रतिभा को तलाशने के लिए यह समर क्लास शुरू की थी।

डेढ़ महीने के बाद कला अकादमी के द्वारा ही प्रसिद्ध हिन्दी लेखकों की कहानी पर इन्हीं बच्चों के द्वारा ऑडिटोरियम में मंचन भी किया जाना था। भोलू, नमन, दिव्या और आंचल के साथ अनेक बच्चे यहां पर साथ-साथ अभिनय का प्रशिक्षण ले रहे थे। समय मिलने पर कला के शिक्षक अमृत कौर, नैना और अमन बच्चों को नैतिक कहानियां व महापुरुषों के प्रसंग भी सुनाते। समय मिलने पर बच्चे खेलते भी थे। सभी बच्चों को प्रेमचंद की कहानियों का मंचन करना था। भोलू, नमन, दिव्या और आंचल के ग्रुप को प्रेमचंद की कहानी 'पंच परमेश्वर' का मंचन करना था। एक दिन भोलू की तबीयत खराब हो गई और वह अभिनय कक्षा में नहीं जा पाया। भोलू को 'जुम्मन मियां' का मुख्य किरदार सौंपा गया था। इसलिए शिक्षकों के साथ ही सभी बच्चों को भी चिंता लग गई कि आखिर भोलू कब ठीक होगा? अमृत मैडम बोलीं, 'भोलू तो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। ऐसे में उसकी कमी बहुत खल रही है। आखिर भोलू को हुआ क्या है?' अगले दिन नमन ने अमृत मैडम से कहा, 'मैडम, भोलू की तबीयत प्रदूषित वातावरण और गंदे पानी से खराब हुई है। कल उसे उसकी मम्मी डॉक्टर के पास लेकर गई थीं। भोलू तो आज यहां आना चाह रहा था। वह बोल रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं।' लेकिन डॉक्टर ने उसे दो दिन आराम करने के लिए बोला है।' नमन की बात पर दिव्या बोली, 'मैडम, हमारी जगदंबा बस्ती के पास ही लोग कूड़ा डालते हैं, जिससे पूरी कॉलोनी में बदबू आने लगी है।'

दिव्या की बात सुनकर अमन सर बोले, 'क्या वहां सफाई कर्मचारी नहीं आते?' आंचल बोली, 'सर, आते हैं, लेकिन वह तो ऊपर-ऊपर सफाई करके चले जाते हैं।' बच्चों की बातें सुनकर अमृत, नैना और अमन बहुत दुखी हुए। अमृत, नैना और अमन तीनों ही यंग टीचर थे। तीनों ने अपनी कक्षा के पचास बच्चों को उस दिन एक्टिंग की शिक्षा देने के बजाय स्वच्छता का पाठ पढ़ाया और अगले दिन उनकी कॉलोनी के पास बने कूड़े के ढेर को साफ करने का वायदा भी किया। उन्होंने कक्षा के सभी बच्चों से कहा कि कल पुराने और साफ कपड़े पहनकर आएं। अगले दिन कक्षा में नैना ने सभी बच्चों को रबड़ के दस्ताने दिए, अमन ने मुंह पर लगाने वाले मास्क बांटे। अमृत कौर के पिता की भवन निर्माण सामग्री की दुकान थी। इसलिए वह अपने यहां से सीमेंट और टूट-फूट की मरम्मत का कच्चा माल लेकर आई हुई थी। सभी बच्चे अपने शिक्षकों के साथ जगदंबा कॉलोनी में जा पहुंचे। इसके बाद वहां की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हुआ। बच्चों व शिक्षकों को काम पर लगे देखकर जो लोग घरों में मौजूद थे, वे भी वहां हाथ बंटाने के लिए आ पहुंचे। सीमेंट व पत्थरों से गड्ढों को भरना शुरू किया गया। अमन ने एमसीडी को फोन कर के कचरा गाड़ी भी मंगवा ली थी। जिस कूड़े को लोग घरों के आस-पास फेंक देते थे, उसे उठवाया गया और वहां पर एक बड़ी कचरा पेटी लगाई गई। इसके साथ ही प्रत्येक घर को ढंके हुए डस्टबिन दिए गए ताकि वे अपने कूड़े को उसमें डालें और बंद करके रखें।

कुछ ही घंटों में जगदंबा कॉलोनी की सूरत बदल चुकी थी। अब वहां रहने वाले लोगों को अपनी गली पहचान में ही नहीं आ रही थी। बस्ती के सभी लोगों ने बच्चों के साथ कला के शिक्षकों को भी धन्यवाद किया। दो दिन बाद भोलू कुछ ठीक हुआ और अपनी क्लास में आया। वह जुम्मन मियां के किरदार को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर रहा था। इसी तरह हंसी-खुशी में डेढ़ महीना बीत गया और 22 जून की तारीख आ गई। इस दिन कमानी ऑडिटोरियम में बच्चों की कला और अभिनय की परीक्षा थी। सभी ने अपने डायलॉग याद किए हुए थे। कला अकादमी की ओर से स्वास्थ्य मंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। कला अकादमी द्वारा बारह केंद्रों पर विभिन्न स्थानों के बच्चों को प्रशिक्षित किया गया था। सभी की कहानियों का मंचन 22 जून से 25 जून तक किया जाना था। 'पंच परमेश्वर' की कहानी का मंचन 22 जून को पांच बजे प्रारंभ होना था। पंच परमेश्वर के पात्रों के अनुरूप बच्चों ने पोशाकें पहनी हुई थीं और मेकअप किया हुआ था। जैसे ही कहानी नाटक रूप में प्रस्तुत हुई, वैसे ही सभी पात्रों ने अपने-अपने अभिनय को जीवंत करना शुरू कर दिया। भोलू का जुम्मन मियां का किरदार सभी पर भारी पड़ा।

सभी बच्चों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए और जिनका अभिनय श्रेष्ठ था, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। भोलू को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ। जब भोलू के माता-पिता को मंच पर बुलाया गया तो वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे।



जोकर की हंसी है बड़ी पुरानी

बात जोकर की हो और डैन राइस का जिक्र न हो, यह कैसे हो सकता है। जी हां! डैन राइस ही वो शख्स हैं, जिन्होंने अंकल सैम जैसे मशहूर किरदार का परिचय दुनिया से कराया। राइस का हास्य पैदा करने का तरीका एकदम जुदा था, वे समकालीन घटनाओं से हास्य निकाल लेते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में रेडियो और फोटोग्राफ के बाजार में आने के बाद जोकर भी सुरीला हो चुका था। वह अब खुद संगीत तैयार कर दर्शकों के सामने मधुर हास्य परोसता था। इतना ही नहीं, अब तरह-तरह के जोकर मनोरंजन के लिए तैयार थे। चाहे वो चेहरे पर सफेद रंग लगाए हुए जोकर का परम्परागत रूप हो या फिर लाल चेहरे वाले ढीले-ढाले कपड़े पहने हुए ऑगस्ते जोकर। इसके अलावा, अपने रोचक संवादों से दर्शकों का दिल जीतने वाले चॉकलेट जोकर, जिन्हें मेकअप की खास जरूरत नहीं थी। चेहरे का गहरा रंग होने के कारण वे केवल सफेद रंग का इस्तेमाल करते थे। जेम्स मैकइन्टायर और टॉम हीथ ने सन् 1874 में 'ट्रैम्प क्लाउन' को ईजाद किया, जिसमें काले चेहरेवाले अफ्रीकी जोकर के चेहरे पर सफेद रंग लगाया जाता था। अब जोकर डांस भी कर सकता था, जिसे बाद में टैप डांसिंग के नाम से जाना गया। इस तरह धीरे-धीरे दिन बदला, समय बदला और जोकर भी। अब जोकर उत्सवों और कर्निवाल्स में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने लगा था। सारी दुनिया में इस हास्य किरदार ने अपनी पहचान बना ली थी। आज यह संसार के किसी भी कोने में जाना-पहचाना चेहरा है। हमारे देश में इस दिलचस्प किरदार की कोई कमी नहीं।

सर्कस के परदे के पीछे से लेकर 70 एमएम की स्क्रीन तक जोकर को एक एलग पहचान मिली। ऐसे में सन् 1970 में राज कपूर द्वारा निर्मित एवं निर्देशित 'मेरा नाम जोकर' को कैसे भुलाया जा सकता है। यह भारत में जोकर समुदाय पर बनी बेहतरीन फिल्मों में से एक है, जिसमें राजकपूर ने बड़ी ही संजीदगी से 'राजू जोकर' की भूमिका को निभाया। इसके अलावा, समय-समय पर लगने वाले सर्कस जोकरी परम्परा को आज भी जीवित रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, ताश के 52 पत्तों में भी जोकर की मौजूदगी काफी अहम रहती है। टैरो कार्ड में भी जोकर भविष्य की जानकारी देते हैं। अधिकतर संस्कृतियों में इस किरदार की दखलंदाजी है। आमतौर पर हर जश्न को खुशनुमा बनानेवाले इस शख्स को अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। तो आओ जानते हैं किस देश ने इसे क्या नाम दिया

जोकर भी होते हैं अंधविश्वास के शिकार...

जोकर कभी भी चेहरे पर नीला रंग इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनके अनुसार, यह रंग अशुभता की निशानी है। इतना ही नहीं, प्रदर्शन से पहले जोकर अपने साथियों को शुभकामना नहीं देते, ऐसा करना उनके लिए श्राप देने जैसा है।





मुंबई के पार्क में नाबालिगों ने कपल को पीटा, छेड़छाड़ का विरोध करने पर भड़के, BJP नेता ने बता दिया 'मुस्लिम गुंडई'

मुंबईः मुंबई से एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां के कुर्ला पश्चिम इलाके में फीनिक्स मार्केटसिटी मॉल के पास एक युवक-युवती के साथ 8 से 10 नाबालिग लड़कों ने बदसलूकी और मारपीट की है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद घाटकोपर पुलिस स्टेशन में 8 नाबालिगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. मामले में 5 नाबालिगों के अभिभावकों को भी नोटिस जारी किया गया है. इन लड़कों ने पार्क में घूमने आए जोड़े को घेरकर पहले उनके साथ बदसलूकी की और फिर मारपीट करने लगे. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन सभी 8 नाबालिगों को बाल न्याय बोर्ड किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी



इस मामले में बड़ी बात कही है. पीड़ित युवक-युवती प्रमोद महाजन उद्यान में घूमने गए थे और वहां फोटो खींच रहे थे, इसी दौरान वहां मौजूद 8 से 10 नाबालिग लड़कों के ग्रुप ने उन पर अश्लील टिप्पणियां शुरू कर दीं. कपल ने जब इस कमेंटबाजी और छेड़छाड़ का विरोध किया, तो बात बिगड़ गई, आरोप है कि नाबालिग लड़कों ने दोनों को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी. वीडियो में एक लड़का चप्पल जैसी चीज से युवक को मारता दिख रहा है, तो दूसरा लड़का लड़की के सिर पर लकड़ी या डंडे से मारता दिख रहा है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद इस मामले में नाराजगी जाहिर की है.

इस मामले में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसे 'मुस्लिम' गुंडागर्दी बताया है, उन्होंने लिखा घाटकोपर के फीनिक्स मॉल के पास, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदू युवाओं पर हमला किया, पुलिस ने BNS की धाराओं 189(2), 189(4), 118(1), 352 और 351(2) के तहत 8 नाबालिगों (कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चों) के खिलाफ FIR दर्ज की है. इसके अलावा, 5 बच्चों के माता-पिता को नोटिस जारी किए गए हैं. मैं आज दोपहर 4 बजे उस इलाके में जाऊंगा.

ट्रेन में मिली लाश, सोने की अंगूठी से हुई पहचान; भिखारी ने रेप के बाद तोड़ दी पसलियां

नई दिल्ली। कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल रेलवे यार्ड में एक खाली रेलवे कोच के अंदर रेप और मर्डर की शिकार हुई 54 वर्षीय महिला की पहचान, तमिलनाडु रेलवे पुलिस की बारीकी से की गई जांच में मिली एक सोने की अंगूठी की मदद से हो सकी. इस अंगूठी पर हॉलमार्क के निशान थे, जो जांच में एक अहम सुराग साबित हुए. यह घटना 13 तारीख की आधी रात को रेलवे यार्ड में खड़े एक कोच के अंदर हुई. महिला का शव तब मिला, जब कोच को साफ करके किसी दूसरी ट्रेन में लगाने की तैयारी की जा रही थी.

रेलवे SP (त्रिची) आदर्श



पचेरा के अनुसार, अंगूठी पर मौजूद हॉलमार्क के निशान से जांचकर्ताओं को पता चला कि यह गुजरात से आई थी. वहां के विक्रेता ने पुष्टि की कि यह अंगूठी छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक रिटेलर को बेची गई थी. इस सुराग के आधार पर, पुलिस महिला का पैन (PAN) विवरण और मध्य प्रदेश का वह पता हासिल करने में कामयाब रही, जो उसने गहने खरीदते समय दिया था. पीड़िता की पहचान होना एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन पुलिस ने रेप और हत्या के इस मामले को बहुत तेजी से सुलझा लिया और जांच शुरू होने के छह घंटे के भीतर ही संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया. जांचकर्ताओं ने शुरुआत में तीन लोगों को संदिग्ध माना. रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज से जांच का दायरा सीमित करने में काफी मदद मिली. फुटेज में सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति को ट्रेन के एक डिब्बे से बाहर निकलते देखा गया. बाद में उससे पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

सौरभ दास को राहुल गांधी लगे 'डीसेंट', CJP को कमजोर करने के आरोप कांग्रेस पर ही लगा रहे हैं पुराने साथी

नई दिल्ली। कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पार्टी ने CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कमजोर करने का काम किया था। वहीं, सीजेपी नेता सौरभ दास ने लोकसभा सांसद राहुल गांधी की तारीफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल बहुत सभ्य इंसान हैं। हालांकि, दास ने यह भी साफ कर दिया है कि CJP किसी भी पार्टी के साथ जाने की योजना नहीं बना रही है।

असम में कांग्रेस के साथ गठबंधन में रह चुकी रायजोर दल ने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए थे। पार्टी प्रमुख अखिल गोगोई की तरफ से लिखे गए पत्र में दावा किया गया था कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को दुश्मन मानती है। साथ

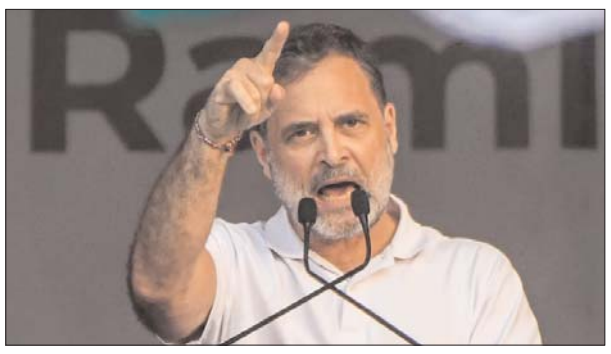


ही कहा था कि कांग्रेस ने ही CJP के आंदोलन को कमजोर किया था। फिलहाल, इसपर कांग्रेस या सीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। गोगोई ने लिखा था, 'सड़कों पर आंदोलन को विभाजित करके और एक वास्तविक जनविद्रोह के साथ कॉम्पिटिशन करके आपकी पार्टी ने CJP के आंदोलन को कमजोर किया। इससे सत्तारूढ़ सरकार को आंदोलन को नियंत्रित करने का मौका मिला और देश के सामने निर्णायक संघर्ष का जो अच्छा अवसर था वह गंवा दिया गया। उन्होंने लिखा, 'यह लगातार स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस भाजपा के बजाय क्षेत्रीय दलों और वास्तविक जन आंदोलनों को अपना मुख्य दुश्मन मानती है।' गोगोई ने आरोप लगाया, 'कांग्रेस भाजपा को अपना वैचारिक प्रतिद्वंद्वी बताती है, लेकिन वह लगातार क्षेत्रीय सहयोगियों और स्वतंत्र जमीनी आंदोलनों को कमजोर करने का काम करती है। सीजेपी नेता सौरभ दास ने राहुल गांधी की तारीफ की है। द एकेएस पॉडकास्ट में पहुंचे दास ने कहा था, 'मुझे लगता है बहुत ही डीसेंट इंसान हैं। सोनिया गांधी जी ने उनको बहुत अच्छी परवरिश दी होगी और मुझे लगता है किसी से भी आप पूछोगे तो वो बताएंगे। एक यूनिफॉर्म ओपिनियन रहेगा। मुझे लगता है कि बहुत कट्टर दूसरे साइड में जो सपोर्टर होंगे वो ना बोले।

'ये हादसा नहीं, लापरवाही का नतीजा', मणिपुर में जहरीली शराब से मौत पर राहुल ने BJP को घेरा

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर में जहरीली शराब पीने से हुई कई लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है. इस घटना को लेकर उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा करार दिया है. राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'मणिपुर में जहरीली शराब से कई लोगों की मृत्यु का समाचार बहुत दुखद है. शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं.

राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा, 'यह



हादसा नहीं, बल्कि सरकार की लापरवाही का नतीजा है. पहले हिंसा ने सैकड़ों घर उजाड़े, अब जहरीली शराब उजाड़ रहीं है सरकार अब भी सो रही है. दोषियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई हो और बिना देरी पीड़ित परिवारों को पूरी सहायता और उचित मुआवजा मिले. मणिपुर के चंदेल जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 180 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है. इस घटना के बाद राज्य सरकार ने हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, ये मौतें 18 से 20 नवंबर के बीच मुख्य रूप से चकपिकारोंग उपमंडल और इसके आसपास के इलाकों में हुई हैं. पीड़ितों में मेथनॉल पॉइजनिंग (जहरीली शराब के असर) जैसे लक्षण दिखने के बाद कई गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए इंफाल के अस्पतालों में रेफर किया गया है. पीड़ितों को उल्टी, पेट दर्द, चक्कर आना, सिरदर्द, धुंधला दिखाई देना और सांस लेने में तकलीफ जैसी गंभीर शिकायतें हुई थीं.

बांग्लादेश में हसीना समर्थकों के 50 घरों और दुकानों में आगजनी पूर्व सांसदों के ठिकानों पर भी हमला

ढाका। बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। नराइल जिले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं, पूर्व सांसदों और समर्थकों के करीब 50 घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। कालिया उपजिला के बेंदर चार गांव में हुई घटना के दौरान हमलावरों ने कई घरों में तोड़फोड़ की और फर्नीचर, कीमती सामान सहित अन्य वस्तुएं लूट लीं। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी के दो नेताओं की हत्या के बाद देश में तनाव और बढ़ गया है।

शेख हसीना के दिसंबर में बांग्लादेश लौटने के ऐलान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। पिछले कुछ दिनों में कई जिलों में हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। 15 नवंबर को हसीना के गृह जिले गोपालगंज में अवामी लीग समर्थकों की रैली के बाद बीएनपी कार्यालयों, नेताओं के घरों और दुकानों पर हमले हुए। 17 नवंबर को तुंगीपाड़ा पुलिस थाने पर हमला किया गया और बीएनपी सांसद के घर में आग लगा दी गई।

18 नवंबर को चटगांव में अंतरिम सरकार के पूर्व प्रमुख मोहम्मद यूनुस के पुश्तैनी घर को निशाना बनाया गया। वहीं, 19 नवंबर को देशव्यापी बंद के दौरान गोपालगंज में पुलिस थाने, ग्रामीण बैंक की शाखा और कई घरों में आगजनी हुई। थाने में खड़े करीब 20 वाहन भी जला दिए गए। 20 नवंबर को सिलहट में विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर के घर के बाहर आग लगा दी गई।

गौरतलब है कि छात्र आंदोलन के बाद 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और वह भारत आ गई थीं। इसके बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली और अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया। चुनाव के बाद तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार ने भी यह प्रतिबंध जारी रखा।हसीना ने दिसंबर 2026 में स्वदेश लौटकर कानूनी प्रक्रिया का सामना करने की इच्छा है। बांग्लादेश सरकार लगातार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, जबकि भारत ने कहा है कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

मारुति से बोफोर्स तक, सोनिया गांधी पर किताब लिखेंगे BJP सांसद; 10 सवालों का देंगे जवाब

नई दिल्ली। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को घोषणा की कि वे कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर एक किताब लिखेंगे। उन्होंने कहा कि यह किताब सोनिया गांधी पर कोई दुर्भावनापूर्ण हमला नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक सफर का विस्तृत विवरण होगा। एक्स पर एक पोस्ट में बीजेपी सांसद ने 10 ऐसे सवाल गिनाए, जिनके जवाब इस किताब में दिए जाएंगे।

इन 10 सवालों में शामिल है कि सोनिया गांधी मारुति की मालकिन कैसे बनीं, 'नेशनल हेराल्ड' को कैसे खरीदा गया और 2004 से 2014 के बीच वह प्रधानमंत्री से भी ऊपर कैसे थीं। दुबे ने यह भी कहा कि किताब में



बोफोर्स मामले की असली कहानी, मेनका गांधी और सोनिया गांधी के बीच विवाद के कारण और यह बात भी शामिल होगी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री के बजाय अपने परिवार के साथ चीन ओलंपिक में क्यों गई थीं। बीजेपी सांसद द्वारा उठाए गए अन्य सवालों में सीताराम केसरी की धोती के पीछे की कहानी, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी के बीच लड़ाई की वजह, 1999 में किस कांग्रेस नेता ने उन्हें धोखा दिया और राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी में से वे राजनीतिक रूप से किसे ज्यादा पसंद करती हैं, जैसे विषय शामिल हैं। इससे पहले निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर कई आरोप लगाते हुए मारुति से जुड़ी कंपनियों में कांग्रेस नेता की हिस्सेदारी, शेयरहोल्डिंग और वहां उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए। एक्स पर एक पोस्ट में दुबे ने कंपनी के गठन और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार के साथ इसके कथित संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने सोनिया गांधी को मारुति की असली मालकिन बताया और सवाल उठाया कि एक विदेशी नागरिक होने के बावजूद कंपनी में उनका कथित पद कैसे है। बीजेपी सांसद ने 21 नवंबर, 1970 का जिक्र करते हुए दावा किया कि संजय गांधी ने 'मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' के साथ एक समझौता किया, जो कथित तौर पर सोनिया गांधी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि 1970 में स्थापित होने के बावजूद इस कंपनी को 1968 में ही कारें बनाने के लिए सरकारी मंजूरी कैसे मिल गई। दुबे ने लिखा कि क्या आप जानते हैं कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद, सोनिया गांधी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत शेयरहोल्डर थीं? 21 नवंबर, 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी की 'मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' के साथ एक समझौता किया। सोनिया गांधी ही मारुति की असली मालकिन थीं।

वंदेभारत में छूटा विदेशी पर्यटक का डॉलर-रुपयों से भरा बैग, रेलकर्मी ने लौटाया

वाराणसी। वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। काशी भ्रमण पर आए सिंगापुर के एक विदेशी पर्यटक का रुपये और डॉलर से भरा बैग नई दिल्ली-वाराणसी वंदेभारत एक्सप्रेस में छूट गया। कैंट स्टेशन पहुंची ट्रेन के यार्ड में सफाई के दौरान एक रेलवे कर्मचारी को यह बैग मिला। बैग में करीब 2.11 लाख रुपये के साथ हजारों डॉलर भी रखे थे। कर्मचारी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए बैग को रेलवे अधिकारियों को सौंप दिया। बाद में पहचान और पूछताछ के बाद बैग समेत पूरी रकम पर्यटक को सुरक्षित लौटा दी गई। सिंगापुर निवासी पर्यटक भारत भ्रमण पर आए हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने वाराणसी वंदेभारत ट्रेन से यात्रा की थी।



यात्रा पूरी होने के बाद वह ट्रेन से उतर गए, लेकिन जल्दबाजी में नकदी से भरा अपना बैग ट्रेन में ही भूल गए। ट्रेन के यार्ड में पहुंचने के बाद नियमित सफाई का काम शुरू हुआ। इसी दौरान सफाई कर्मचारी की नजर सीट पर छूटे बैग पर पड़ी। बैग खोलकर देखने पर उसमें भारतीय मुद्रा के साथ विदेशी करेंसी भी मिली। कर्मचारी ने बिना देर किए इसकी जानकारी रेलवे अधिकारियों को दी और बैग उनके सुपुर्द कर दिया।उधर, बैग गुम होने की जानकारी मिलने पर विदेशी पर्यटक अपने गाइड के साथ उसकी तलाश में कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने रेलवे अधिकारियों को बैग और उसमें रखी नकदी के बारे में जानकारी दी। स्टेशन पर यात्री से आवश्यक पूछताछ और पहचान की पुष्टि के बाद अधिकारियों ने उन्हें उनका बैग सौंप दिया। बैग में रखी पूरी रकम सुरक्षित मिलने पर पर्यटक ने राहत की सांस ली। स्टेशन निदेशक अर्पित गुप्ता ने बताया कि ट्रेन की सफाई के दौरान कर्मचारी को बैग मिला था, जिसे नियमानुसार अधिकारियों के सुपुर्द किया गया। यात्री की पुष्टि होने के बाद उनका सामान वापस कर दिया गया। विदेशी पर्यटक ने रेलवे कर्मचारियों की ईमानदारी और तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि भारत में उन्हें इस तरह का अनुभव मिला, जिससे उनका भरोसा और मजबूत हुआ है। उन्होंने भारतीय रेलवे और कर्मचारियों के व्यवहार को सराहनीय बताया।

हमें चाहिए कट्टर हिंदू प्रधानमंत्री, राजा भैया के पिता भदरी नरेश ने कर दी योगी को PM बनाने की मांग

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा में आयोजित बाबा बागेश्वर की श्रीराम कथा के बीच यजमान विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पिता भदरी नरेश राजा उदय प्रताप सिंह ने सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग रख दी। राजा उदय प्रताप सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि हिंदू विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमें एक कट्टर हिंदूवादी प्रधानमंत्री की जरूरत है, और इस समय केवल योगी आदित्यनाथ ही उसके लिए उपयुक्त हैं। उनकी इस पोस्ट पर कई तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। राजा भैया की 91 वर्षीय मां



मंजुला राजे कथा स्थल पर पहुंची और दर्शन किया। राजा भदरी की इस मांग को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यूजर्स अपने-अपने हिसाब से इस मांग के मायने निकाल रहे हैं और अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। उधर, शुक्रवार को तीन दिवसीय कथा के समापन के मौके पर बाबा बागेश्वर ने योगीराज देवरहा बाबा कथा मंडपम में सुबह 11 बजे से दिव्य दरबार लगाया। उन्होंने लोगों की अर्जियां सुनीं। बाबा ने पंडाल में बैठे कन्नौज से आए अरविन्द, अहिबरनपुर के राजकुमार उर्फ राजू, सैफाबाद से अखिलेश कुमार सिंह, राजेन्द्र कुमार, लालगंज की रिंकी कुमारी, बृजेश सिंह, मनोरमा, राम कुमारी, लक्ष्मी राजपूत, कालीचरण आदि की पर्ची खोली। नाम लेकर उनको बुलाया और उनसे अर्जी लगवाई। सनातन को बढ़ाने का संदेश देने के साथ कुंडा में राजा भैया द्वारा आयोजित बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा में प्रदेश और देश की कई सियासी हस्तियां पहुंचीं।

रोहिंग्या शरणार्थी कैंप पहुंचे यूएनजीए अध्यक्ष खलीलुर रहमान आईसीजे के फैसले के बाद म्यांमार को चेतावनी

इस्लामाबाद। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के अध्यक्ष और बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान शुक्रवार, 20 नवंबर को म्यांमार सीमा के पास दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश स्थित रोहिंग्या शरणार्थी कैंप पहुंचे। उनका यह दौरा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के उस ऐतिहासिक फैसले के एक दिन बाद हुआ, जिसमें रोहिंग्याओं के खिलाफ नरसंहार और अत्याचारों के मामले में म्यांमार को जिम्मेदार ठहराया गया था। रहमान को सुनने के लिए कैंप में हजारों रोहिंग्या शरणार्थी एक घाटी में एकत्र हुए। उन्होंने 19 नवंबर को आए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले और म्यांमार पर उसके प्रभाव के बारे में जानकारी दी। रहमान ने कहा कि रोहिंग्या संकट अब केवल बांग्लादेश या शरणार्थियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल और सामूहिक प्रयास करने की अपील की। उन्होंने म्यांमार को चेतावनी देकर कहा कि यदि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का पालन नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2017 में म्यांमार की सेना की कार्रवाई के बाद रखाइन प्रांत से करीब आठ लाख रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश पहुंचे थे। संयुक्त राष्ट्र ने इस सैन्य अभियान को जातीय सफाए का स्पष्ट उदाहरण बताया था। इस दौरान हजारों लोगों की जान गई थी। वर्तमान में करीब 12 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश के विभिन्न शरणार्थी शिविरों में कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं।

देश की पहली बुलेट ट्रेन कब चलेगी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टाइमटेबल का ऐलान किया, सूरत से वापी तक रूट चालू होगा

नई दिल्लीः रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि देश की पहली ट्रेन 2027 की आखिरी तिमाही में शुरू हो जाएगी. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रूट का सूरत से वापी तक पहला सेक्शन 2027 में खुलेगा. उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कई चरणों में तैयार होगा. उन्होंने कहा कि सितंबर तक 456 किमी खंभों का काम और 371 किमी का पुल निर्माण पूरा हो चुका है.वैष्णव ने लिखा कि 299



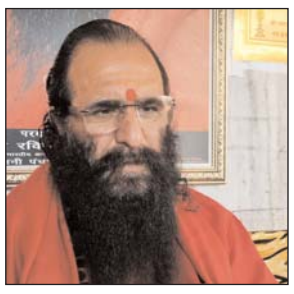
किमी रूट में छह लाख नॉइज बैरियर (शोर रोकने के सिस्टम) लगाए गए हैं. 206 किमी के पुल पर 9300 ह्॥श्व बिजली के खंभे लगाए गए हैं.चार पहाड़ी सुरंगों की खुदाई पूरी हो चुकी है. महाराष्ट्र में 21 किमी लंबी सुरंग के 5 किमी हिस्से की खुदाई माउंटेन टनलिंग से की गई है. उन्होंने बताया कि आठ स्टेशनों पर सिविल वर्क पूरा हो चुका है. वहां आर्किटेक्चरल फिनिशिंग का काम चल रहा है. साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन, सूरत और ठाणे में तीनों ट्रेन रखरखाव केंद्रों पर काम चल रहा है.समुद्र के नीचे बनने वाली सुरंग पर वैष्णव ने कहा कि महाराष्ट्र में ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 21 किमी लंबी सुरंग से गुजरता है. इसमें से सात किमी का हिस्सा समुद्र के अंदर ठाणे क्रीक से होकर जाता है.यह देश की पहली समुद्र के नीचे बनी रेल सुरंग है. जुलाई 2026 में विक्रोली और सावली में दो टनल बोरिंग मशीनें लगाई गई हैं. जो देश की सबसे बड़ी टीबीम मशीनों में से एक है. इनमें से हर एक मशीन का कटरहेड 4 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है. हर मशीन का वजन 3 हजार टन से ज्यादा है. ये 500 एशियाई हाथियों के भार के बराबर है. ये मशीन 96 मीटर लंबी है. लगभग पांच क्रिकेट पिचों के बराबर.

योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर संत समाज ने जताया शोक

मां का जाना जीवन की सबसे बड़ी अपूरणीय क्षति :श्रीमहंत डॉ. रविंद्र पुरी

के.के.पी संवाददाता

हरिद्वार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के पंचतत्व में विलीन होने पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत डॉ. रविंद्र पुरी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।



श्रीमहंत डॉ. रविंद्र पुरी ने कहा कि मां का स्थान संसार में सबसे ऊंचा होता है और मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन की ऐसी अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। सावित्री देवी ने अपने जीवन में जिस सादगी, त्याग, तपस्या और संस्कारों का परिचय दिया, वह सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि एक मां के संस्कार ही संतान के व्यक्तित्व और जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व में धर्म, राष्ट्रसेवा, अनुशासन और समाज के प्रति समर्पण के जो गुण दिखाई देते हैं, उनमें उनकी माता के संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा, 'सावित्री देवी ने अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दिए, जिन्होंने उन्हें संन्यास और राष्ट्रसेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज उनका पंचतत्व में विलीन होना अत्यंत भावुक और पीड़ादायक क्षण है। संत समाज इस दुख की घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके पूरे परिवार के साथ खड़ा है।

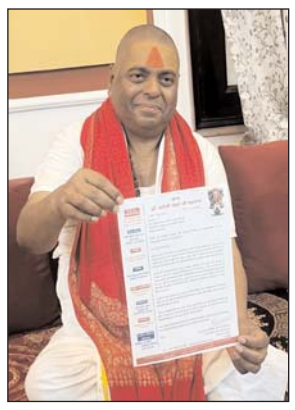
श्रीमहंत ने कहा कि भारतीय सनातन परंपरा में मां को प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। मां के संस्कार व्यक्ति के जीवन में सदैव मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। सावित्री देवी ने अपने परिवार को धर्म और संस्कारों से जोड़े रखा तथा उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायी रहेगा। उन्होंने मां भगवती मनसा देवी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहा कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें और शोक संतप्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उनके पूरे परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि संत समाज की संवेदनाएं हमेशा योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के साथ रहेंगी।

श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण में आपसी विवाद व रचनात्मक गतिविधियों के अभाव से आहत करौली शंकर ने त्यागा महामण्डलेश्वर का पद

अन्य किसी अखाड़े से जुड़ने का नहीं दिया कोई संकेत

के.के.पी संवाददाता

हरिद्वार, 21 नवम्बर। अखाड़े की आपसी खींचतान व रचनात्मक गतिविधियों के अभाव से आहत होकर महामंडलेश्वर पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर जी महाराज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मिश्री मठ के परमाध्यक्ष व श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण के पद पर आरूढ़ हुए करौली शंकर महाराज का वर्तमान परिस्थितियों में श्री पंचायती अखाड़ा नया अखाड़ा उदासीन से मोह भंग होता नजर आ रहा है। प्रेस को जारी अपने त्याग पत्र में उन्होंने अखाड़े के अध्यक्ष श्रीमहंत धुनी दास जी को सम्बोधित त्यागपत्र में साफ कहा है कि आपसी खींचतान, तानाशाही और



मुकदमेबाजी ने अखाड़े की पंचायती व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। साथ ही पंजाब के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व और सम्मान नहीं मिलने पर भी नाराजगी जताई है।

करौली शंकर महाराज ने अपने त्यागपत्र में कहा कि सनातन धर्म, संत परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति समर्पण की भावना से उन्होंने अखाड़े में महामंडलेश्वर के रूप में सेवा की। इसके लिए उन्होंने संत-महात्माओं और पदाधिकारियों का आभार भी जताया। हालांकि मौजूदा हालात को लेकर उन्होंने गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखाड़े के पदाधिकारियों के बीच आपसी खींचतान और तानाशाही के चलते पंजाब के लोगों को न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व और उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके कारण अखाड़े में आपसी मुकदमेबाजी की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों ने जिन उद्देश्यों के साथ अखाड़े की स्थापना की थी, वे पूरे होने के बजाय निजी हितों के लिए अखाड़े की संपत्तियों का शोषण और दोहन किया जा रहा है। त्यागपत्र में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अखाड़े में ध्यान-साधना, पूजा-पाठ जैसी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। इससे अखाड़े की स्थापना के मूल उद्देश्यों को ही झटका लगा है। करौली शंकर महाराज ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों और अपने स्वतंत्र आध्यात्मिक एवं सामाजिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वेच्छा से महामंडलेश्वर पद छोड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने अध्यक्ष से त्यागपत्र स्वीकार कर पद से जुड़े सभी दायित्वों से मुक्त करने का अनुरोध किया है।

एक नजर

217वें वर्ष भी शाही शान से निकली भगवान विट्ठलनाथजी की शोभायात्रा

वडोदरा। संस्कारी नगरी वडोदरा की 216 वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा एक बार फिर पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ जीवंत हुई। देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर मांडवी स्थित श्री विट्ठलनाथजी मंदिर से भगवान की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। लगातार 217वें वर्ष आयोजित इस पारंपरिक वरघोड़े में शाही आन-बान-शान के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

इस ऐतिहासिक शोभायात्रा की शुरुआत राजपरिवार के पूजा-अर्चना करने के बाद हुई। परंपरा के अनुसार राजपरिवार ने सबसे पहले भगवान विट्ठलनाथजी का पूजन किया। इसके बाद भगवान को विधि-विधान से पालकी में विराजमान किया गया और भक्तों की उपस्थिति में शोभायात्रा रवाना हुई।

भगवान विट्ठलनाथजी की शोभायात्रा मांडवी से एमजी रोड, लहेरीपुरा, न्यायमंदिर, प्रताप टॉकीज, अहमदाबादी पोल, रावपुरा और कोठी होते हुए आराधना टॉकीज के रास्ते गनेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। यहां विवाह की धार्मिक रस्में संपन्न होने के बाद दोपहर 2 बजे शोभायात्रा की वापसी में नागरवाड़ा, घीकांटा रोड, अहमदाबादी पोल, जुबिलीबाग, प्रताप टॉकीज और न्यायमंदिर होते हुए भगवान अपने निज मंदिर पहुंची।

इस आयोजन की खास बात यह भी रही कि धार्मिक आस्था के इस पर्व में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने शिरकत की। शहर के प्रमुख पदाधिकारियों, नगर अध्यक्षों और पार्षदों की मौजूदगी ने सामाजिक एकता का संदेश दिया। राजनीतिक मतभेदों से परे दोनों दलों के नेताओं का एक साथ शामिल होना आयोजन के सामाजिक महत्व को भी दर्शाता है।

भगवान विट्ठलनाथजी का यह वरघोड़ा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि वडोदरा की ऐतिहासिक विरासत और सामूहिक आस्था का प्रतीक है। समय बदला, पीढ़ियां बदलीं और शहर का स्वरूप भी आधुनिक होता गया, लेकिन राजपरिवार के पूजन से शुरू होने वाली यह परंपरा आज भी उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जा रही है।

बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पालकी में विराजमान भगवान के दर्शन किए और शोभायात्रा में शामिल होकर इस ऐतिहासिक परंपरा के साक्षी बने। 217वें वर्ष भी पूरे वैभव के साथ निकला यह वरघोड़ा साबित करता है कि वडोदरा की पहचान केवल विकास और आधुनिकता से नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने की परंपरा से भी है।

रणबीर कपूर और यश की 'रामायण' पर प्रतिबंध लगाने की मांग, विहिप का आरोप- रावण का महिमामंडन कर महर्षि वाल्मीकि की रामायण को तोड़ा-मरोड़ा

नई दिल्ली । रणबीर कपूर और यश अभिनीत फिल्म 'रामायण' को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) से इसका प्रमाणपत्र वापस लेने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि फिल्म में महर्षि वाल्मीकि की मूल रामायण के प्रसंगों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और रावण का महिमामंडन किया गया है।

विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार और महासचिव बजरंग लाल बागड़ा ने फिल्म के कथानक और पात्रों के चित्रण पर आपत्ति जताई है। बजरंग लाल बागड़ा ने कहा कि फिल्म में कई काल्पनिक घटनाएं जोड़ी गई हैं, जबकि रामायण के महत्वपूर्ण पात्रों और प्रसंगों को जानबूझकर हटाया गया है। संगठन ने आरोप लगाया कि इससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से पहाड़ी स्वाद को मिलेगी नई पहचान, महिला समूहों को मिलीं 17 फूड वैन; 60 प्रतिशत सब्सिडी पर मिला स्वरोजगार का अवसर

10 लाख रुपये की प्रत्येक फूड वैन पर सरकार दे रही 6 लाख की सब्सिडी, महिला समूहों को लौटाने होंगे केवल 4 लाख रुपये ; पहाड़ी व्यंजनों के जरिए आत्मनिर्भर बनेंगी ग्रामीण महिलाएं

के.के.पी संवाददाता

कालाढूंगी (नैनीताल)। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी दिशा में राज्य सरकार ग्रामीण महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के साथ प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय खानपान को नई पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में नारी शक्ति सम्मेलन के अवसर पर विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गरिमामयी उपस्थिति में जनपद नैनीताल के महिला समूहों एवं सहकारिताओं को 17 वे-साइड ईटरी (फूड वैन) की सौगात दी



गई।

ग्रामोत्थान (REAP-UGVS) परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई यह पहल महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे के मार्गदर्शन में शुरू हुई इस पहल से जनपद के सभी आठ विकासखंडों के महिला समूहों एवं सहकारिताओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट एवं राज्यसभा सांसद दिनेश आर्य ने फूड वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया! 10 लाख की फूड वैन, सरकार दे रही 6 लाख की सब्सिडी

इस पहल की खास बात यह है कि महिला समूहों को प्रत्येक फूड वैन लगभग 10 लाख रुपये की लागत पर उपलब्ध कराई गई है। इसमें राज्य सरकार की ओर से 6 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि संबंधित महिला समूहों को केवल 4 लाख रुपये की धनराशि वापस करनी होगी। यानी कुल लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे महिलाओं पर शुरुआती आर्थिक बोझ कम होगा और वे अपेक्षाकृत कम निवेश में अपना स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी।

फूड वैन में मिलेगा उत्तराखंड के पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद

इन फूड वैन के माध्यम से पर्यटकों और आम नागरिकों को उत्तराखंड के पारंपरिक एवं स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखने को मिलेगा। इनमें मंडुवे यानी रागी के मोमोज, भट्ट की चुड़कानी, भट्ट के डुबके, गहत की दाल के डुबके, मंगोड़ी, भांग की चटनी सहित अन्य पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन एवं स्थानीय उत्पाद तैयार कर ग्राहकों को परोसे जाएंगे।

इससे उत्तराखंड के पारंपरिक खानपान को आधुनिक फूड सर्विस के माध्यम से बाजार उपलब्ध होगा। विशेष रूप से मंडुवा, भट्ट और गहत जैसे स्थानीय अनाज एवं दालों की मांग बढ़ने से इनके उत्पादन और बिक्री को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

पहाड़ी उत्पादों को बाजार, स्थानीय किसानों और महिलाओं को लाभ

इस पहल से केवल महिला समूहों की आमदनी बढ़ाने का ही अवसर नहीं मिलेगा, बल्कि स्थानीय कृषि उत्पादों को भी एक नया बाजार मिल सकेगा। मंडुवा, भट्ट और गहत जैसे पारंपरिक उत्पादों का व्यंजनों में उपयोग बढ़ने से स्थानीय किसानों को अपने उत्पादों की बिक्री के नए अवसर मिल सकते हैं।

वहीं, पहाड़ी खानपान को बढ़ावा मिलने से उत्तराखंड की पारंपरिक खाद्य संस्कृति को भी नई पहचान मिलेगी। पर्यटक भी फूड वैन के माध्यम से स्थानीय स्वाद और पारंपरिक व्यंजनों का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।

यूओयू की सराहनीय पहल : 23 नवंबर से सैन्य अध्ययन केंद्रों तथा जेलों में स्थापित विशेष अध्ययन केंद्रों के शिक्षार्थियों के लिए विशेष ऑनलाइन परामर्श सत्रों का आयोजन

के.के.पी संवाददाता

हल्द्वानी। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी द्वारा दूरस्थ शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ एवं शिक्षार्थी-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। माननीय कुलपति प्रो. नवीन चन्द्र लोहनी के मार्गदर्शन एवं दूरदर्शी नेतृत्व में विश्वविद्यालय द्वारा सैन्य अध्ययन केंद्रों तथा जेलों में स्थापित विशेष अध्ययन केंद्रों के शिक्षार्थियों सहित 10 या 10 से कम पंजीकृत शिक्षार्थियों की संख्या वाले सभी अध्ययन केंद्रों के विद्यार्थियों के लिए विशेष ऑनलाइन परामर्श सत्रों का आयोजन किया जा रहा है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पंजीकृत शिक्षार्थी तक पहुंचकर उसे गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक परामर्श एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है, ताकि कम नामांकन, भौगोलिक दूरी अथवा विशेष परिस्थितियों के कारण किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा प्रभावित न हो। ग्रीष्मकालीन सत्र जुलाई 2026 के अंतर्गत इन विशेष परामर्श सत्रों का संचालन आदर्श अध्ययन केंद्र, हल्द्वानी (16000) द्वारा दिनांक 23 नवंबर 2026 से 07 जनवरी 2027 तक ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। ये सत्र सोमवार से शुक्रवार तक निर्धारित विषयवार समय-सारणी के अनुसार प्रातः 10:30 बजे से सायं 04:30 बजे तक आयोजित होंगे।

इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के कुल 32 विषयों के विद्यार्थियों को परामर्श प्रदान किया जाएगा। इनमें संस्कृत, गणित, हिंदी, रसायन विज्ञान, इतिहास, वनस्पति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, पत्रकारिता, लोक प्रशासन, प्राणी विज्ञान, अंग्रेजी, वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान, ज्योतिष, कंप्यूटर विज्ञान, मनोविज्ञान, वाणिज्य, कृषि एवं विकास अध्ययन, योग, शिक्षा, विधि, उर्दू, पर्यटन, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन, समाज कार्य, पुस्तकालय विज्ञान, समाजशास्त्र, संगीत, अर्थशास्त्र, कर्मकांड तथा भूगोल एवं जीआईएस विषय शामिल हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जूम प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन परामर्श सत्रों में शामिल होने हेतु मीटिंग लिंक, मीटिंग आईडी एवं पासकोड उपलब्ध कराया गया है। संबंधित शिक्षार्थी निर्धारित विषयवार तिथि एवं समय के अनुसार इन सत्रों में प्रतिभाग कर सकेंगे। आदर्श अध्ययन केंद्र, हल्द्वानी (16000) के समन्वयक डॉ. विशाल कुमार शर्मा ने बताया कि माननीय कुलपति प्रो. नवीन चन्द्र लोहनी के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय प्रत्येक शिक्षार्थी को उच्च शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की इस पहल के माध्यम से सैन्य अध्ययन केंद्रों में अध्ययनरत जवानों एवं जेलों में स्थापित विशेष अध्ययन केंद्रों के शिक्षार्थियों को भी नियमित शैक्षणिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही कम नामांकन वाले अध्ययन केंद्रों के प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचकर उनकी शैक्षणिक समस्याओं का समाधान करना तथा उन्हें अध्ययन के प्रति प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है।

'ईसाइयों से ज्यादा होंगे मुसलमान', डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व अफसर बोलीं- ज्यादा बच्चे पैदा करें अमेरिकी, बहस तेज

नई दिल्लीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने एक नई डिबेट शुरू कर दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके अमेरिकियों को शादी करने और ज्यादा बच्चे पैदा करने को कहा है. इसके अलावा उनका पालन चर्च के संस्कारों के साथ करने की अपील की है. अपनी इस अपील के साथ लेविट ने एक्स पोस्ट में 'द वॉशिंगटन पोस्ट' की एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है. इस रिपोर्ट में एक स्टडी को प्रकाशित किया गया है, जिसका शीर्षक है- '2035 तक दुनिया में सबसे अधिक होगी मुस्लिम आबादी'. इसके अलावा इसी खबर में यह भी अनुमान जताया गया है कि अमेरिका ईसाई बहुल मुल्क नहीं रह जाएगा.



इसी खबर को लेकर लेविट ने जो पोस्ट किया है, उस पर बहस तेज है. उनका कहना है कि अमेरिकी लोग जल्दी शादियां करें. ज्यादा बच्चे पैदा करें और परिवार बनाएं. चर्च के संस्कारों में उनकी परवरिश करें और अमेरिका से प्यार करना सिखाएं. उनकी इस पोस्ट पर कुछ लोगों ने समर्थक किया है तो वहीं कुछ यूजर्स ने इसे गलत बताया है. एक वर्ग का कहना है कि लेविट की बात सही है. ईसाई धर्म के अनुसार बच्चों की परवरिश होनी ही चाहिए और फैमिली वैल्यूज भी जरूरी हैं. वहीं कुछ लोगों ने उनकी पोस्ट पर ऐतराज जताया है. इन लोगों का कहना है कि आखिर कैसे लोगों को किसी एक पंथ को ही मानने के लिए कहा जा सकता है.

इसके अलावा कुछ लोगों ने बच्चे पालने को लेकर यह भी कहा कि महंगाई इतनी बढ़ रही है. कॉस्ट ऑफ लिविंग में इजाफा हुआ. इसलिए बच्चे पालना, स्वास्थ्य की देखभाल और उनकी पढ़ाई आसान नहीं है. इसके अलावा यह भी कहना है कि बच्चों को यह छूट देनी चाहिए कि वे जो धर्म चाहें, उसके मूल्यों का पालन करें. एक यूजर ने लिखा कि मुस्लिम और ईसाई के बीच बच्चे पैदा करने का कंपीटीशन नहीं होना चाहिए. इसका सही समाधान यह है कि बाहर से आने वाले लोगों पर ब्रेक लगाया जाए. इससे ही पश्चिमी देशों का कल्चर बचा रह सकेगा.

वहीं एक यूजर ने लिखा कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात लिख रही हैं.

देना था जज को गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया ओवैसी को, प्रशासनिक चूक का यह वीडियो हो रहा वायरल

नई दिल्लीः क्या हो जब तैयारी हो किसी और को गार्ड ऑफ ऑनर देने की और दे दी जाए किसी और को. ऐसा ही कुछ हुआ है यूपी के सहारनपुर में. जहां पुलिस ने जज साहेब की जगह AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को ही गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया. प्रशासन की चूक का यह वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से ओवैसी अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ सर्किट हाउस पहुंचे हैं. जहां पहले से ही पुलिसकर्मी गार्ड ऑफ ऑनर देने की तैयारी में हैं. इसी बीच पार्टी कार्यकर्ता ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर लेने के लिए कहते हैं. हालांकि इस वीडियो में दिख रहा है कि ओवैसी भी प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर जरा असहज महसूस कर रहे हैं. उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी इस बात का



एहसास है कि आखिर कुछ तो कहीं गड़बड़ है. लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ या पूछ पाते वो गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे पुलिसकर्मियों को सैल्यूट करते हैं और वहां चले जाते हैं. खास बात ये है कि प्रशासन की तरफ से जो गार्ड ऑफ ऑनर ओवैसी को दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया जाना था. इस घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं.ऐसे में जज की जगह ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने की बात सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर हुई चूक को लेकर सवाल उठने लगे हैं. इस घटना के बाद से ही अब यह चर्चा है कि आखिर अधिकारियों से इतनी बड़ी गफलत कैसे हो गई. क्या यह केवल प्रशासनिक चूक थी या फिर ये जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का गंभीर मामला है. घटना ने सरकारी प्रोटोकॉल के पालन और प्रशासनिक समन्वय को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

ऐसा काम न करें कि पार्टी से निकालना पड़ जाए, बंगाल में क्या हुआ कि सुनील बंसल ने BJP नेताओं को दी सख्त चेतावनी

कोलकाताः 'कोई भी ऐसा काम न करें जिससे पार्टी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़े. यदि कोई नेता या पदाधिकारी गलत आचरण में लिप्त पाया जाता है तो उसकी पद या हैसियत चाहे जो भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा.' यह सख्त संदेश बंगाल में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी हाईकमान ने दी है. दरअसल शुक्रवार को कोलकाता स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा की एक अहम बैठक हुई. इस बैठक में जिला अध्यक्षों, संभागीय प्रभारियों, विभिन्न पदाधिकारियों और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे.बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और केंद्रीय पर्यवेक्षक सुनील बंसल ने की. बंद कमरे में हुई इस मीटिंग



में उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सख्त संदेश देते हुए चेताया. मालूम हो कि 4 मई को राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद अभी केवल छह महीने ही हुए हैं, लेकिन इस दौरान पार्टी के भीतर गुटबाजी, नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी और संगठन विरोधी गतिविधियों जैसी शिकायतें सामने आई हैं. ऐसी शिकायतें संगठन तक पहुंची हैं, जिससे पार्टी और संगठनात्मक ढांचे दोनों को नुकसान हो रहा है. इसके अलावा कुछ विधायकों पर संगठनात्मक बैठकों में स्वयं उपस्थित होने के बजाय प्रतिनिधि भेजने के आरोप भी लगे हैं. इसी पृष्ठभूमि में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक सुनील बंसल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश दिया है. बैठक में मौजूद एक नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि संगठन को दरकिनार कर कोई कार्रवाई या गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी. अगर कोई अनियमितता में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. यह चेतावनी कार्यकर्ताओं से लेकर विधायकों, सांसदों और मंत्रियों तक सभी के लिए है.

ब्लड रिलेशन में शादी करने पर लगेगी रोक? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली। नजदीकी खून के रिश्ते में शादी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने करीबी रिश्ते में शादी करने को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि रक्त संबंधियों के बीच विवाह करने से नुकसान होता है और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। दरअसल बेंगलुरु की रहने वाली एक दृष्टिबाधित स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि उसके माता-पिता रक्त संबंधी हैं। उन दोनों की वजह से उसे जन्मजात अनवांशिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट इस तरह की शादियों पर रोक नहीं लगा सकता है। हालांकि इसको लेकर कानून बनाया जा सकता है और वह



संसद के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए पुछा है कि क्या इस तरह की शादियां रोकने के लिए कोई कानून लाया जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी किससे करना है यह तो किसी की भी निजी पसंद होती है। कोर्ट इसपर रोक नहीं लगा सकता । लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि करीबी रक्त संबंधियों से शादी करने पर सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में या तो रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए या फिर लोगों को जागरूकर करना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि दक्षिण के राज्यों में करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी का प्रचलन ज्यादा है। इस तरह की लगभग 30 फीसदी शादियां होती हैं। इस वजह से सेहत से जुड़ी दिक्कतें भी होती रहती हैं। इसपर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस बात को लेकर आंगनवाड़ी या फिर पंचायत के स्तर पर जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे की वैज्ञानिक सोच और कारण को लोगों के सामने रखा जाना चाहिए।

आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में करीबी संबंधियों के बीच शादी को मंजूरी है। हालांकि हिंदू मैरिज ऐक्ट में कुछ रिश्तों में शादी करने पर रोक है। हालांकि इसको लेकर कोई बहुत कड़ा कानून नहीं है।

ऐडवोकेट अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से फाइल की गई याचिका में चिकित्सा विज्ञान का हवाला देकर बताया कि ब्लड रिलेशन में शादियां करने पर बच्चों में विकृतियां आ सकती हैं। ऐसे मामलों में जन्मजात विकृति, अंधा या बहरा होना, विकास में कमी, विकलांगता, शिशुओं की मृत्यु और खराब स्वास्थ्य का खतरा बना रहता है।

अयोध्या से नेपाल के जनकपुर धाम ट्रेन में 8 AC और 7 स्लीपर कोच, सीतामढ़ी-नरकटियागंज से गोरखपुर भी रूट में शामिल

अयोध्या। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की नगरी अयोध्या और माता सीता की जन्मस्थली नेपाल के जनकपुर धाम के बीच अब सफर बेहद आसान होने वाला है. दोनों प्रमुख धार्मिक शहरों को सीधे जोड़ने वाली जनकपुर धाम-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस ट्रेन (15595/15596) का उद्घाटन 23 नवंबर को किया जाएगा. रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आम यात्रियों के लिए इस ट्रेन का नियमित संचालन 28 नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है. भारतीय रेलवे बोर्ड ने इस नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने की हरी झंडी दे दी है. यह ट्रेन उत्तर प्रदेश और बिहार के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों से गुजरते हुए भारत और



नेपाल के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई रफ्तार देगी.नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह और पीएम मोदी संयुक्त तौर पर इसका उद्घाटन करेंगे. जनकपुर धाम-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस ट्रेन का रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक, जनकपुर धाम और अयोध्या कैंट के बीच की करीब 604 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन लगभग 19 घंटे में तय करेगी.

इस सफर में सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि श्रद्धालुओं को नेपाल जाने के लिए बीच रास्ते में ट्रेन बदलने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी.

पंचतत्व में विलीन हुईं योगी आदित्यनाथ की मां, सीएम के सबसे छोटे भाई ने दी मुखाग्नि

हरिद्वार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी पंचतत्व में विलीन हो गईं। हरिद्वार के चंडी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। सीएम योगी आदित्य नाथ के सबसे छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट ने दिवंगत मां सावित्री देवी को मुखाग्नि दी। शुक्रवार को सावित्री देवी का निधन हो गया था। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता के निधन पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई भाजपा



नेता चंडी घाट स्थित श्मशान घाट पहुंचे। देवबंद विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कुंवर बृजेश ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मां के जाने का दुख हर कोई समझ सकता है। मां का स्थान जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है और उनके निधन से होने वाली पीड़ा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। उन्होंने इस दुख की घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी मां सावित्री से आखिरी मुलाकात सात माह पूर्व हुई थी। तब योगी दो दिनी दौरे पर अपने पैतृक गांव पंचूर आए थे। 7 और 8 मई के इस दौरे में उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के साथ परिवार संग समय बिताया था। आठ मई को पैतृक आवास पर मां से उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। वर्ष 1998 में संन्यास के चार साल बाद जब योगी पंचूर पहुंचे, तो परंपरा के तहत उन्होंने अपनी मां से पहली भिक्षा ली।

स्टालिन को हराने वाले विजय थलपति के विधायक की मौत

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में कोलाथुर विधानसभा सीट पर एक बार फिर सबकी नजरें टिक गई हैं। सीएम विजय थलपति की पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कझगम के विधायक वीएस बाबू के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है। अब यहां उपचुनाव होना है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन एक बार फिर कोलाथुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे?

वीएस बाबू ने विधानसभा चुनाव में स्टालिन को हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया था। स्टालिन 2011 से लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने



डीएमके के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी थीं। पार्टी को विधानसभा चुनाव में सत्ता भी गंवानी पड़ी थी। अभिनेता से नेता बने विजय की नई पार्टी टीवीके ने डीएमके को सत्ता से बाहर कर दिया था।

वीएस बाबू के निधन के बाद कोलाथुर सीट पर होने वाला उपचुनाव डीएमके के लिए अपनी खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने का मौका बन सकता है। पार्टी के भीतर कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि एमके स्टालिन इस सीट से दोबारा चुनाव लड़ें।

डीएमके सांसद सी रविंद्रन ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि स्टालिन को कोलाथुर से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, इसका फैसला पूरी तरह उन्हीं के हाथ में है। हालांकि, पार्टी कार्यकर्ता उन्हें दोबारा चुनाव मैदान में देखना चाहते हैं। रविंद्रन ने कहा, 'यह हमारे नेता का निर्वाचन क्षेत्र है। फैसला उनका है और केवल वही इस पर निर्णय ले सकते हैं। डीएमके कार्यकर्ता के तौर पर हम चाहेंगे कि वह चुनाव लड़ें, लेकिन अंतिम फैसला हमारे नेता ही करेंगे। '

विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी कैसे बन गईं मारुति की MD ? निशिकांत दुबे ने पूछा

नई दिल्ली। आत्मकथा प्रकाशित होने के बाद सोनिया गांधी को लेकर कई नई जानकारी सामने आई है। इस सबके बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता पर कई नए आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद इंदिरा गांधी की सरकार ने सोनिया गांधी को मारुति कंपनी का डायरेक्टर बना दिया था। उनके शेयर भी तय किए गए थे। उन्होंने इसे अनुचित लाभ देने जैसा बताया है।

'कांग्रेस का काला अध्याय'



नाम की सीरीज में निशिकांत दुबे ने लिखा, 'क्या आप जानते हैं कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत शेयरहोल्डर थीं? भारत सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी विदेशी नागरिक किसी भारतीय कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो फिर वह 1970 में डायरेक्टर कैसे बन गईं?

निशिकांत दुबे ने आगे लिखा, '21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी की मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। सोनिया गांधी ही मारुति की असली मालकिन थीं। मारुति कंपनी की स्थापना 1970 में हुई थी, लेकिन इसे 1968 में ही भारत सरकार से एक पत्र मिल गया था जिसमें इसे कारें बनाने की अनुमति दी गई थी।

उन्होंने आगे कहा, '1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक कैबिनेट आदेश जारी किया, जिससे उनकी बहू सोनिया गांधी की कंपनी को कारें बनाने की इजाजत मिल गई। 3 अप्रैल 1972 को संजय गांधी ने इस कंपनी के लिए भारत सरकार के खर्च पर दुनिया भर की यात्रा की।'

उन्होंने यह भी दावा किया कि इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस कंपनी को स्थापित करने में भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि उनके करीबी सहयोगी और निजी सचिव आरके धवन भी इससे जुड़े हुए थे।

निशिकांत दुबे ने सवाल किया, 'प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर एक निजी कंपनी का दफ्तर कैसे खुल गया? प्रधानमंत्री के निजी सचिव आरके धवन इसके निदेशक कैसे बन गए?

इस दौरान निशिकांत दुबे ने मारुति परियोजना के लिए जमीन आवंटन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'उस समय हरियाणा सरकार के नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन आवंटित नहीं की जा सकती थी।

बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने दामाद को दिया डिफेंडर, 18 तोला जेवर और सोने-चांदी के बर्तन...

मोकामाः बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह का कल तिलक समारोह था. बाहुबली अनंत सिंह समेत तमाम परिजन शुक्रवार को तिलक लेकर दामाद ऋषिकेश के घर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने दामाद को डिफेंडर कार भेंट की और कई अन्य लग्जरी उपहार भी प्रदान किए. इन तोहफों में 100 ग्राम वजन की एक सोने की चेन और 80 ग्राम वजन का सोने का ब्रेसलेट भी शामिल हैं. दोनों आभूषणों को मिला लें तो कुल कीमत करीब 30 लाख रुपये मानी जा सकती है. यही नहीं बड़ी संख्या में सोने और चांदी के बर्तन भी अनंत सिंह ने भेंट किए हैं. जानकारी



के मुताबिक 100 किलो से ज्यादा मात्रा में देशी घी के लड्डुओं समेत बड़े पैमाने पर मिठाइयां और फल आदि भी दिए गए. अनंत सिंह अपने तीनों बेटों के साथ कार्यक्रम में सजधज कर पहुंचे थे और डिफेंडर की चाबी दामाद को सौंपने के बाद निकल गए. उनके कार्यक्रम स्थल से निकलने के बाद भी समर्थकों की भारी भीड़ मौके पर जुटी रही.

पटना के दानापुर स्थित एक निजी रिसॉर्ट में भव्य तिलक समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान भूमिहार समाज की परंपरा का भी जिक्र हुआ. इस परंपरा के मुताबिक बेटी के पिता तिलक चढ़ाए जाने के दौरान मौजूद नहीं रहते. अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को है. मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर 2026 को बाढ़ क्षेत्र स्थित उनके पैतृक गांव नदवां में होगी. उनकी शादी पटना के बिहटा (कृष्णानगर) निवासी ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित से तय हुई है, जिनके पिता सीआरपीएफ कमांडेंट रणविजय कुमार सिंह हैं.

राहुल गांधी सहारनपुर से मिशन यूपी की शुरुआत करेंगे, पुराने वोट बैंक को साधने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस?

नई दिल्लीः इसी हफ़्ते सोमवार को राहुल गांधी ने यूपी कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में इस बात को लेकर चिंता जताई कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं जबकि कांग्रेस का प्रचार अभियान नज़र नहीं आ रहा. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने पार्टी के दोनों बड़े चेहरों यानी राहुल गांधी और खरगे को मैदान में उतारने की रणनीति बना ली है. दस दिसंबर के आसपास राहुल गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिशन यूपी की शुरुआत करेंगे. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक दस दिसम्बर के आसपास सहारनपुर में राहुल गांधी एक बड़ी रैली को संबोधित कर सकते हैं. इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के भी शामिल होने की



संभावना है. सूत्रों के मुताबिक इस रैली की थीम 'संविधान बचाओ' रखी जाएगी. वहीं, 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे लखनऊ में 'संविधान रक्षा मार्च' में शामिल होंगे. कथित वोट चोरी के खिलाफ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस 26 नवंबर को देश भर में प्रदर्शन कर रही है. सहारनपुर से शुरुआत कर राहुल गांधी यूपी में करीब आधा दर्जन रैलियों को संबोधित करेंगे. इसमें पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस का दौरा भी शामिल है. बनारस में राहुल गांधी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे. सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर दर्शन को लेकर भी अंदरखाने चर्चा हुई लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया. इससे पहले सहारनपुर में राहुल शाकंभरी देवी के मंदिर जा सकते हैं. जहाँ तक सहारनपुर से शुरुआत की बात है तो स्थानीय सांसद इमरान मसूद को हाल में ही यूपी कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. मुस्लिम बहुल इस इलाके में पिछले दिनों एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भी सभा की थी.

उनके सहयोगी आज़ाद समाज पार्टी अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी सहारनपुर के रहने वाले हैं. राहुल और खरगे की रैली के जरिए कांग्रेस की कोशिश मुस्लिम-दलित मतदाताओं को साधने की होगी ताकि ये आजाद-ओवैसी गठबंधन की तरफ़ ना छिटकें.

अयोध्या में सपा पर बरसे आकाश आनंद, बसपा नेता ने कहा, 'संविधान फाड़ने वाले आज संविधान लेकर घूम रहे हैं'

नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है. बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने शुक्रवार को अयोध्या जाकर इसे और गरमा दिया. वहां उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सपा ने प्रमोशन में आरक्षण देने वाले विधेयक का विरोध किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के सदस्य ने उस विधेयक की प्रतियां संसद में फाड़ी थीं. इसके साथ ही उन्होंने सपा पर बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों के नाम बदलने का भी आरोप लगाया. आकाश आनंद ने अयोध्या में कहा,''2012 में जब संसद में



अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का विधेयक पेश किया गया था, तब किस पार्टी ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था? वह समाजवादी पार्टी थी. उन्होंने तो लोकसभा में इस विधेयक की प्रति छीनकर फाड़ दी थीं.'' उन्होंने कहा कि आज वही लोग हाथों में संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं. पहले वे संविधान को फाड़ते हैं और फिर उसे हाथ में लेकर दावा करते हैं कि वे हमारे रक्षक हैं! उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था की बात न ही करें तो बेहतर है. साल 2013 को याद कीजिए, जब उनकी सरकार थी. मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ की एक घटना ने दंगे का रूप ले लिया था. इस हिंसा में 60 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और हजारों परिवारों को कई महीनों तक राहत शिविरों में रहना पड़ा था. कानून-व्यवस्था पर उनकी पकड़ का यह हाल था. बसपा नेता ने आरोप लगाया कि बहनजी (मायावती) की सरकार के दौरान बहुजन आंदोलन के महान महापुरुषों के नाम पर जिलों के नाम रखे गए थे. लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी के सत्ता में आते ही इन नामों को एक-एक करके हटा दिया गया था.उन्होंने कहा,''ये सिर्फ नाम नहीं थे और न ही किसी साइनबोर्ड पर लिखे कुछ शब्द थे. इन नामों के जरिए हमारी आने वाली पीढ़ियां अपना इतिहास जान सकती थीं, लेकिन जानबूझकर इन नामों को मिटा दिया गया.कांशीराम नगर को वापस कासगंज कर दिया गया।

'रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई', आजम खान के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM का तंज

लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच आजम खान के जेल से छूटते ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. आजम खान के पुलाव वाले बयान पर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता ने तंज कसा है. दरअसल आजम खान ने ओवैसी की पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि यूपी के लोग हैदराबादी बिरयानी नहीं, बल्कि पुलाव और मटन बिरयानी खाते हैं. इस ओवैसी की पार्टी के नेता इसरार अहमद ने आजम के इस बयान को



'रस्सी जल गई, पर बल नहीं गया' वाला करार दिया. उन्होंने कहा कि आजम को जेल से रिहा होने के लिए हम दिल से बधाई देते हैं. उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक वह जेल में बंद थे. रिहाई के बाद सपा नेता के बयान को देखकर ऐसा लगता है कि 'रस्सी जल गई, पर बल नहीं गया'.AIMIM नेता ने कहा कि आजम यूपी में पुलाव खाने की बात करते हैं. लंबे समय तक सपा का पुलाव खाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की हालत और भी खराब हो गई. लेकिन अब मुसलमान जाग चुके हैं. वे अब समाजवादी पार्टी के लोकलुभावने वादों के झांसे में नहीं आएंगे.

केरल में महिला कांग्रेस का 'जन्तर-मन्तर' प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

तिरुवनंतपुरम। केरल में महिला कांग्रेस ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित लोक भवन के सामने आयोजित इस प्रदर्शन को 'केरल जन्तर-मन्तर' नाम दिया गया। इसमें महिला कांग्रेस की सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन का उद्घाटन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव दीपा दासमुंशी ने किया। दीपा दासमुंशी ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक पार्टी देशभर में विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वह प्रभावित लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाए।

स्वामी/ प्रकाशक / मुद्रक
प्रमोद कुमार ने जय माँ गंगा प्रिंटर्स, हरिद्वार से मुद्रित कराकर कार्तिकेय कॉलोनी, फेस-3, दर्पण स्कूल वाली गली, निकट हनुमान मंदिर, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी जनपद-नैनीताल (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया।
सम्पादक
प्रमोद कुमार
मो.7830201066
सह-सम्पादक
दया जोशी
मो.9412135616